सैन्य सन्देश

Sainya Sandesh

युगाब्द 5126 | पौष–माघ, 2081 | जनवरी, 25

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद् का मुखपत्र

बस्ती (उ0प्र0)

जोधपुर (राजस्थान)

कुशीनगर (उ0प्र0)

बुलन्दशहर (उ0प्र0)

कोलकाता (द0 बंगाल)

कानपुर (उ0प्र0)

गोरखपुर (उ0प्र0)

उत्तराखण्ड

लखनऊ (उ0प्र0)

भरतपुर (राजस्थान)

धुले (महाराष्ट्र)

दिल्ली

नैनीताल (उत्तराखण्ड)

देवरिया (उ0प्र0)

पुणे (महाराष्ट्र)

बस्ती (उ0प्र0)

RNI Reg No.UPBIL/2002/9228

27. December 2023 Postal Reg. SSP/LW/NewsPaper-01-2024-2026
Despatched from- Lko RMS Non TD.
Dates of Despatch- 5,22 & 28

दिल्ली

कुशीनगर (उ0प्र0)

महराजगंज (उ0प्र0)

जयपुर (राजस्थान)

रीवां (म0प्र0)

मेरठ (उ0प्र0)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद

के सदस्य बनें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दें

मो. : 8317082620, 8004402890
Website: www.sainyasandesh.co.in
E-mail : sainyasandesh@gmail.com, info@sainyasandesh.co.in

सेवा में

अ.भा. पूर्व सैनिक सेवा परिषद् के लिए अतिथि मुद्रक एवं प्रकाशक कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी ने हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा, हजरतगंज, लखनऊ से मुद्रित कराकर, 3 नीवन मार्केट, बी.एन.रोड, कैसरबाग, लखनऊ से प्रकाशित किया।

सैन्य-सन्देश (मासिक)

राष्ट्रहित, समाजहित, सैनिक-हित को समर्पित पत्रिका

अखिल भारतीय पूर्व-सैनिक सेवा परिषद का मुख-पत्र

वर्ष–25 | पौष–माघ–2081 | जनवरी, 2025

संरक्षक मण्डल

ले.ज.वी.के.चतुर्वेदी PVSM, AVSM,SM

ए.वी.एम. एच.पी. सिंह, VrC, VSM

प्रबन्धक मण्डल

ब्रिगेडियर डी एस त्रिपाठी

ब्रिगेडियर गोविन्दजी मिश्र VSM,PPM

सम्पादकीय सलाहकार

ले.जन. दुष्यन्त सिंह PVSM,AVSM

मुख्य सम्पादक

कर्नल लक्ष्मीकान्त तिवारी

सह-सम्पादक

सू.मे. जे.बी.एस. चौहान

प्रबन्धन विपणन एवं प्रचार-प्रसार

मेजर वीरेन्द्र सिंह तोमर

सू.मे. कुंवर सिंह देवपा

सीपीओ घनश्याम प्रसाद केसरी

सीपीओ डीडी पाण्डेय

(सभी पद अवैतनिक)

मुद्रित :

हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा प्रा0 लि0

प्रस्तुति

हिन्दी अनुभाग

1. संपादक की कलम से जलवायु रक्षण हमारे हित में 2
2. आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें 3–4
3. आर्थिक विकास की धुरी बनते गांव 5–6
4. नए भारत के परिकल्पना पुरुष 7–8
5. अजातशत्रु अटल 9–10
6. राष्ट्र सुरक्षा के लिए अमर वीर योद्धाओं का सम्मान 11–12
7. संत अद्वितीय गंध वाले पुष्प 13–14
8. बांग्लादेश की मिलिट्री को 'पढ़ाएगा' पाकिस्तान 15–16
9. मेजर दलपत सिंह शेखावत... 17
10. उपभोक्तावाद के खतरे... 18–20
11. काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास... 21–22

English Section

1.Disgraceful, say veterans as Army HQ removes... 23-24
2. The ceasefire between Israel and the.... 25-26
3. The three dangers that India faces 27-28
4. Netaji Subhas Chandra Bose – Early Life 29
5. Soft power may not be enough to resolve.... 30-31
6. Cousins at war': Pakistan-Afghan ties... 32-33
7. Afghan Taliban hit 'several points'.... 34-35
8. गतिविधियां 36

सम्पादकीय कार्यालय : 3, नवीन मार्केट, बी.एन. रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

मो. : 8004402890, 8317082620, 9651217002

Website: www.sainyasandesh.co.in

E-mail : sainyasandesh@gmail.com

The Publishers and Authors reserve the rights in regard to the contents of 'Sainya Sandesh'. The images and certain content used herein are from public domain, belongs to their respective owners and the same is being used herein for awareness and educational purposes only. The Magazine is non commercial, non profitable and intended to create awareness amongst soldiers community.

जलवायु रक्षण हमारे हित में

जब जलवायु में वृद्धि देखी जाती है तब हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता होती है। आज मानवीय गतिविधियों के कारण हमारी जलवायु तेजी से बदल रही है। ग्रह का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और पिछला 10 साल सबसे गर्म दशक रहा है। जमीन पर तापमान और भी तेजी से बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से जमीन की सतह पर तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। हम ऐसे बदलाव देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। वायुमंडल और महासागर गर्म हो गए हैं बर्फ और बर्फ की मात्रा कम हो गई है और समुद्र का स्तर बढ़ गया है।

हम जो परिवर्तन देख रहे हैं वह औद्योगिक क्रांति के बाद से हमारे महासागरों ने कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 30 परसेंट हिस्सा सोख लिया है, जिससे पानी और अधिक अम्लीय हो गया है। पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा, और जंगल या खेत में जला आग जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ और सुख के आसार खेतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि जंगल की आग से हमारे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है।

मौसम की घटनाएं भी लगातार और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। यदि भोजन और पानी की कमी हो जाए तो कुछ स्थान रहने लायक भी नहीं रह पाएंगे, जिसका अर्थ है कि हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर अन्यत्र रहने की जगह ढूंढनी होगी। 20वीं शताब्दी में देखे गए परिवर्तनों में वैश्विक वायु और महासागर के तापमान में वृद्धि, वैश्विक समुद्र के स्तर में वृद्धि, बर्फ और बर्फ के आवरण में दीर्घकालिक निरंतर व्यापक कमी और वायुमंडलीय एवं महासागर परिसंचरण के साथ–साथ क्षेत्रीय मौसम पैटर्न में परिवर्तन शामिल है।

जलवायु परिवर्तन के कर्म को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. प्राकृतिक कारण – जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं जिनमें प्रमुख हैं महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी, समुद्री तरंगे और धरती का घुमाव।

2. मानवीय कारण– पृथ्वी के सतह पर कुछ गैस शामिल हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वह जल के कण, जो वातावरण के एक प्रतिशत से भी कम भाग में होते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जिस प्रकार के हरे रंग का कांच उष्मा को अंदर आने से रोकता है कुछ इसी प्रकार से यह गैस पृथ्वी के ऊपर एक परत बनाकर अधिक उर्जा से इसकी रक्षा करती हैं। इसी कारण इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है।

हम ग्रीन हाउस गैसों में अपना योगदान कोयला पेट्रोल डीजल आदि जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके देते हैं। अधिक जमीन की चाहत में हम पेड़ों को काट देते हैं। प्लास्टिक जैसे सामान का अत्यधिक उपयोग करते हैं। खेती में उर्वरक व कीटनाशकों का आधिकारिक प्रयोग करते हैं।

इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ रक्षात्मक उपाय कर सकते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए। पेड़ों को बचाया जाए व अधिक वृक्षारोपण किया जाए। प्लास्टिक जैसे अपघटन वस्तुओं का उपयोग न किया जाए।

कर्नल लक्ष्मी कान्त तिवारी
मुख्य संपादक

हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता है कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है, जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को यूंही न्योछावर कर देता है!

Our tricolor does not fly because the wind is moving, but our tricolor flutters with the last breath of the young man who sacrificed his life to protect our tricolor!

आर्थिक विकास के लिए भी प्रदूषण रोकें

—डा. भरत झुनझुनवाला

वायु प्रदूषण और आर्थिक विकास में सीधा संबंध दिखता है। कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण उद्योग में उड़ने वाली धूल को रोका जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ेगी और आर्थिक विकास सुस्त पड़ेगा। इसी प्रकार गाड़ियों और उद्योगों के उत्सर्जन एवं किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण अवश्य होता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में माल की लागत घटती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है। हालांकि प्रदूषण का यह केवल सीधा प्रभाव है। इसी प्रदूषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास के विपरीत होते हैं। जैसे भारत में वायु प्रदूषित होने के कारण विदेशी निवेशक और विदेशी पर्यटक नहीं आना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्रभावित होने से लोगों की औसत आयु घटती है। जो व्यक्ति 70 वर्ष तक कार्य करके आर्थिक विकास में योगदान कर सकता था, वही व्यक्ति प्रदूषण के कारण बीमार पड़ने से पचास साल की उम्र में ही निष्क्रिय होने लगता है। समग्रता में देखें तो प्रदूषण को रोकना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद है। यह हमारी अदूरदर्शिता ही है। कि हम प्रदूषण के केवल सीधे नकारात्मक प्रभाव को देखते हैं और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा करते हैं।

प्रदूषण पर बढ़ती हुई चिंता को देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर कुछ कदम उठाए हैं। पहला, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, दूसरा घर–घर में एलपीजी सिलेंडर का वितरण करना और तीसरा शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार। इन कदमों को उठाने के लिए सरकार को साधुवाद, लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण में सबसे बड़ी समस्या कार्यान्वयन की है। गाड़ियों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के विरुद्ध पुलिस द्वारा कम ही कदम उठाए जाते हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन उद्योग के लिए भी व्यापक कानूनी प्रविधान हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने एलान किया कि 21 कंस्ट्रक्शन इकाइयों पर वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में 8.35 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया है। किसी कंस्ट्रक्शन परियोजना में हजारों करोड़ रुपये के दांव को देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरा है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने कभी–कभी कंस्ट्रक्शन, दिल्ली में बदरपुर बिजली संयंत्र एवं डीजल जेनरेटरों पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु ये संकट के समय उठाए जाने वाले अल्पकालिक कदम हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मरीज को तत्काल राहत के लिए आइसीयू में भर्ती किया जाता है। ऐसे कदमों से मूल समस्या का समाधान नहीं होता। इसी प्रकार उद्योगों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से निपटने में समस्या उपायों को अमल में लाने के स्तर पर जुड़ी हुई है। अधिकारी उनके मामले में सख्त कदम नहीं उठाते।

अर्थशास्त्र में 'पब्लिक गुड्स' बेहतरी पक्ति का अवधानी है। जैसे एक करोड़ रुपये की लागत से कोई सड़क बनाई जाए। यदि सड़क न बनाई जाए तो उस पर जो लाखों लोग चलते हैं, उनके जूते घिसने, समय की बर्बादी एवं गाड़ियों के टायर खराब होने का खर्च मान लीजिए तीन करोड़ आता है। ऐसे में सड़क बनाना आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद

है। एक करोड़ के खर्च से तीन करोड़ का लाभ मिल सकता है। ऐसे कार्यों को पब्लिक गुड्स कहा जाता है जो मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता से एक करोड़ का टैक्स वसूल करके सड़क बनाए। इससे जनता भी खुश होगी, क्योंकि उसे तीन करोड़ की बचत होगी जबकि एक करोड़ का टैक्स देना होगा।

इस प्रकार यह विषय नीति का नहीं, बल्कि कार्यान्वयन का बनता है। सरकार को चाहिए कि वह अदूरदर्शिता छोड़े और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पब्लिक गुड्स पर ध्यान केंद्रित करे। गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन एवं उद्योगों पर सख्ती करनी चाहिए। इस सख्ती से जितना जनता को नुकसान होगा, उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। समस्या यही है कि इन पर कार्रवाई से यातायात का खर्च बढ़ता है, मकान बनाने का खर्च बढ़ता है और उद्योगों द्वारा उत्पादन का खर्च बढ़ता है और आर्थिक विकास मंद पड़ता है। इसके बावजूद यदि सरकार इस पर अमल करे तो आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विदेशी निवेश और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ जनता की सेहत सुधारने में मदद मिलेगी।

तीन बिंदुओं पर सरकार को नीतियां सुधारनी चाहिए। पहला पराली दहन के संबंध में है। हमें समझना चाहिए कि पराली एक आर्गेनिक उत्पाद है, जिसका उपयोग कागज अथवा बिजली बनाने में किया जा सकता है। इसे खेतों में जलाना अत्यंत हानिप्रद है, क्योंकि हम वायु प्रदूषण के साथ–साथ अपनी बहुमूल्य वस्तु को जला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआइ को निर्देश दे कि वह जिस प्रकार गेहूं और धान की खरीद करता है, वैसे ही वह पराली खरीदे। फिर उसे कागज उद्योग अथवा बिजली संयंत्रों को बेचा जा सकता है। सरकार को इसमें कुछ घाटा होगा, क्योंकि पराली को खेत से बटोर कर निगम के गोदाम तक लाने में खर्च आएगा, जबकि पराली का विक्रय संभवतः कम मूल्य पर होगा। इस घाटे को सरकार को वहन करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वायु एक पब्लिक गुड है। और उसके लिए इस खर्च का वहन किया जाना चाहिए। दूसरा कदम जलविद्युत से जुड़ा है। यह सही है कि जलविद्युत से सीधे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, लेकिन जल विद्युत से टिहरी जैसी बड़ी झीलों के जरिये मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरण के लिए कार्बन से भी अधिक हानिप्रद है। जलविद्युत परियोजनाओं में जंगल के जंगल पानी में डूब जाते हैं। इससे भी वायु प्रदूषण पर असर पड़ता है। सरकार ऊर्जा के मोर्चे पर सौर एवं पवन ऊर्जा को व्यापक प्रोत्साहन दे और उस सूची में से जलविद्युत परियोजनाओं को हटाए। तीसरी नीति एयर कंडीशनर यानी एसी से जुड़ी है। एसी में बिजली की खपत ज्यादा होती है, जो अंततः प्रदूषण का कारण बनती है। इसलिए सरकार एसी पर टैक्स अधिक लगाए, जिससे उसके स्थान पर पंखों और डेजर्ट कूलर का ज्यादा उपयोग हो। प्रदूषण को लेकर अक्सर पटाखों और आतिशबाजी को भी दोष दिया जाता है, लेकिन यह उतना बड़ा नहीं, अपितु एक तात्कालिक मुद्दा भर है। इसके बावजूद ग्रीन पटाखों को प्रोत्साहन उपयोगी हो सकती है।

आर्थिक विकास की धुरी बनते गांव

—डा. जयंतीलाल भंडारी

हाल में आई एसबीआइ रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी सहायता कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभावों और विकास कार्यों के कारण देश में गरीबी में कमी आई है। यह पिछले वर्ष में घटकर पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है। गरीबी में यह कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से हुई है। जहां वित्त वर्ष 2011– 12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत और शहरी गरीबी 13. 7 प्रतिशत थी, वहीं 2023–24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86 प्रतिशत और शहरी गरीबी घटकर 4.09 प्रतिशत पर आ गई। वित्त वर्ष 2009–10 से 2023–24 के बीच शहरी इलाकों में हर माह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च 1,984 रुपये से बढ़कर 6,996 रुपये और ग्रामीण इलाकों में यह खर्च 1,054 रुपये से बढ़कर 4,122 रुपये हो गया। इस प्रकार देखें तो पिछले 14 वर्षों में आमदनी बढ़ने से जहां शहरों में हर माह प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता खर्च 3.5 गुना हो गया, वहीं यह ग्रामीण इलाकों में करीब चार गुना हो गया। साफ है कि शहरों की तुलना में गांवों में खर्च में हुई वृद्धि ज्यादा है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित दुनिया में गरीबी संबंधी रिपोर्ट – 2024 में भी कहा गया है कि भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या 1990 में 43.1 करोड़ थी। यह संख्या घटते हुए 2021 में 16.74 करोड़ और 2024 में करीब 12.9 करोड़ रह गई।

नीति आयोग की तरफ से वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी इंडेक्स (एमपीआइ)–2024 के मुताबिक देश में पिछले दस वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। इससे जाहिर होता है कि भारत में तेजी से बढ़ता विकास आम आदमी की आमदनी बढ़ा रहा है और गरीबी में तेजी से घटने की प्रवृत्ति उभर रही है। इसके साथ ही शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी तेजी से घट रही है और उनकी आमदनी एवं क्रय शक्ति में भी तेज वृद्धि हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने इसके तहत 80 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाना सुनिश्चित किया है। देश भर में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से यह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि 2016 से राशन की दुकानों में प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिली है। 2011–12 की खपत संख्या के आधार पर शांता कुमार समिति ने कहा था कि पीडीएस व्यवस्था में करीब 46 प्रतिशत लीकेज है। इस समय यह लीकेज घटकर 28 प्रतिशत रह गया है। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में पीडीएस को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए पांच करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद कर दिए गए हैं।

डिजिटल इंडिया, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ ईंधन के लिए उज्वला योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य आदि योजनाओं से भी देश में गरीबी में कमी आ रही है। खासतौर से करीब 54 करोड़ से अधिक जनधन

खातों, करीब 138 करोड़ आधार कार्ड तथा करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं की शक्ति वाले जैम (जेएएम यानी जनधन, आधार, मोबाइल) से सुगठित डिजिटल ढांचा गरीबों के सशक्तीकरण में असाधारण भूमिका निभा रहा है। जैम के बल पर देश के गरीब लोगों के खातों में सीधे आर्थिक राहत हस्तांतरित हो रही है। वर्ष 2014 से 2024 तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा हो चुकी है। इन सबसे गरीबी में बड़ी कमी आई है और ग्रामीण भारत विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है।

आज गांवों के लाखों घरों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। लोगों को डेढ़ लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल तकनीक की मदद से डाक्टर और अस्पताल भी गांवों से कनेक्ट हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिये किसानों को छह हजार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते 10 वर्षों में कृषि ऋण साढ़े तीन गुना बढ़ गए हैं। अब पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। फसलों पर दी जाने वाली सब्सिडी और फसल बीमा की राशि को भी बढ़ाया गया है। स्वामित्व योजना के जरिये गांव के लोगों को संपत्ति के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिये मदद की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार नए वर्ष में गरीबी को और घटाने के लिए गरीबों के सशक्तीकरण की मौजूदा योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के साथ नई योजनाओं एवं नए रणनीतिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेगी और बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक लोगों को 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लक्ष्य पर ध्यान देगी। सरकार को चाहिए कि विकसित भारत के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने की डगर पर आगे बढ़े। इससे भी ग्रामीणों की आमदनी में तेजी वृद्धि होगी और ग्रामीण गरीबी में और कमी आएगी।

नए भारत के परिकल्पना पुरुष

–नरेन्द्र मोदी

मैंने जी भर जिया, मैं मन से मरूं लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसिक, कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे। उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वह यह भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है.. कौन जानता किधर सवेरा आज अगर वह हमारे बीच होते, तो अपनी जन्मतिथि पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वह दिन नहीं भूलता, जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से पीठ पर धौल जमा दी थी। वह स्नेह, वह अपनत्व, वह प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है।

25 दिसंबर का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनकी राजनीति और उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा और गति दी। 1998 के जिस कालखंड में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। नौ साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि यह सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का माडल दिया और भारत को नव विकास की गारंटी दी। वह ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव आज तक अटल है। वह भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आइटी और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में ही तकनीक को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया गया। दूर–दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वह आज भी स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी उनकी गठबंधन सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासनकाल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी। जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। वह चाहते थे कि भारत के सभी वर्गों यानी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए शिक्षा सहज और सुलभ हो।

अटल सरकार के कई ऐसे साहसिक कार्य हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब

भी 11 मई 1998 का वह गौरव दिवस याद है, जब एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोकरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन अटल जी की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को एक और परीक्षण किया गया । इस दूसरे परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो अलग मिट्टी से बना है। उनके शासनकाल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। कारगिल युद्ध का दौर आया। संसद पर आतंकियों ने कायरना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत का हित सर्वोपरि रहा।

अटल जी की बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। विरोधी भी उनके भाषणों के मुरीद थे। उनका यह कथन श्सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिएश, गूंजता रहता है। एनडीए की स्थापना आज भी मंत्र की तरह सबके मन में के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं दिया था। इसके बाद भी उन्होंने कभी किया। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़–तोड़ की राजनीति न चुनकर, पीएम पद से इस्तीफा देने कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट का रास्ता चुना। राजनीतिक षड्यंत्रों के अंतर के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वह आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने।

मैं जानता हूं कि आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय का निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन उनके लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा संविधान था। विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने हिंदी में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने भाजपा की नींव तब रखी, जब कांग्रेस का विकल्प बनना आसान नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी और डा मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने विचारधारा को खुले मन से हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग चुना। वह देश को यह समझाने में सफल एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए है। अटल जी की सौवीं जयंती सुशासन हम सब इस अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें. एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास हैं, सुशासन, एकता और गति के अटल सिखाए सिद्धांत हमें भारत को नव प्रगति भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे।

सैन्य संदेश के सदस्य बनें

पत्रिका 'सैन्य संदेश' का सदस्य बनें। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हर पदाधिकारी को पत्रिका का आजीवन सदस्य (Life Time Member) बनना अपेक्षित है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क रू0 300/– और आजीवन सदस्यता शुल्क रू0 2500/– है। वार्षिक सदस्यों को एक वर्ष बाद पुनः सदस्यता नवीनीकरण अनिवार्य है जिसके लिये प्रति वर्ष रू0 300/– देय है। सदस्यता शुल्क आनलाइन पेयमेंट (Editor Sainya Sandesh A/c No. 0293000109102061 Punjab National Bank, IFS Code PUNB0029300) पर देय है। ऑनलाइन पेयमेंट का स्क्रीन शॉट सैन्य संदेश नेशनल whatsapp ग्रुप में या सम्पादक/सहसम्पादक/ कोषाध्यक्ष के फोन पर जो पत्रिका में सबसे पीछे के पृष्ठ पर अंकित है, भेजें। साथ में सब्सक्राइबर सदस्य का पोस्टल एड्रेस पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर के साथ अवश्य भेजें।

जन्मशती पर विशेष

अजातशत्रु अटल

–अशोक कुमार टंडन

दुश्मन के घर में गर्मजोशी से स्वागत

1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही अटलजी ने 17 एवं 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में दृढ़ता से स्थापित किया था। इस परीक्षण की गोपनीयता ने अमेरिका सहित पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। परमाणु परीक्षणों के पश्चात भारत को अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के आर्थिक एवं सामरिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था।

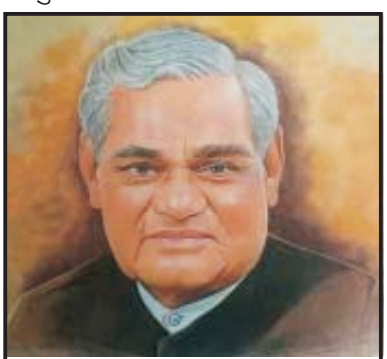

अटलजी का जीवनमंत्र

बाधाएं आती हैं आएं
घिरें प्रलय की घोर घटाएं
पावों के नीचे अंगारे
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं
निज हाथों से हंसते–हंसते
आग लगाकर जलना होगा
कदम मिलाकर चलना होगा

अटलजी की बहुत इच्छा थी कि जम्मू–कश्मीर की समस्या का कोई सार्थक, सम्मानजनक एवं स्थाई हल निकालने का प्रयास किया जाए। यहीं से अटलजी की लाहौर बस यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अमृतसर हवाई अड्डे से वाघा बार्डर पार कर जब अटलजी की बस लाहौर की गलियों से गुजरती हुई गवर्नर हाउस की ओर जा रही थी, तो बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे अपने घरों की खिड़कियों से इकते हुए हाथ हिला कर उनका अभिवादन कर रहे थे। यह एक अद्‌भुत दृश्य था।

मुझे याद है जब अटलजी लाहौर के गवर्नर इस के लान से सीधे प्रसारण द्वारा पाकिस्तान के लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारत से शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर एक पारिश्ता खुद उनके पास आया है। बहुत लड़ लिए। आखिर हम कब तक आपस में लड़ते रहेंगे। आइये मिलकर लड़ें गरीबी से बीमारी से। आपस में सहयोग करें ताकि दोनों पड़ोसी मिलकर विकास की राह पर चलें। हम दोस्त बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। शांति की यह भावनात्मक अपील अटलजी के दिल से निकल रही थी और पाकिस्तान की आवाम तक सीधे पहुंच रही थी। बाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अटलजी से कहा, 'बाजपेयी जी अब तो आप पाकिस्तान से भी इलेक्शन जीत सकते हैं।

लाहौर यात्रा के दौरान वाघा बार्डर पर अटलजी का स्वागत करने यदि कोई नहीं पहुंचा तो वह थे उस समय के पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ शायद वह उस समय अपनी सेना द्वारा रचित कारगिल षड़यंत्र को अंतिम रूप दे रहे होंगे, जिसे उन्होंने अटलजी की यात्रा के तुरंत बाद अंजाम दिया। यह केवल अटलजी की राजनीतिक शुचिता ही थी कि देश की जनता ने पाकिस्तान द्वारा भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले इस जघन्य अपराध की उनकी कूटनीतिक पराजय नहीं समझा। पाकिस्तान के इस शर्मनाक रवैये से इतर, विश्व में शांति स्थापित करने के अटलजी के

प्रयास की भूरि– भूरि प्रशंसा हुई थी। विश्व में अटलजी की छवि शांति के पुरोधा के रूप में उभरी थी, इसीलिए कारगिल में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ पर चीन सहित विश्व समुदाय ने भर्त्सना की थी। कविहृदय अटलजी की लाहौर शांति यात्रा को उनकी कमजोरी समझने वाले जनरल मुशर्रफ को उनके अटल इरादों का अहसास तब हुआ अब भारतीय सेना के जांबाजों ने कारगिल की चोटियों पर चोरी–नृपे कब्जा जमाए घुसपैठिए पाक सैनिकों को पूरी तरह से खदेड़ कर पक्रम का परिचय दिया। इसीलिए तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

दोस्तों के लिए हमेशा खुले दरवाजे

अटलजी की वाकपटुता के तो कई किस्से हैं मगर यह कम ही लोग जानते हैं कि कम शब्दों में, कई बार तो संकेतों द्वारा अपनी मंशा व्यक्त करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। विपक्ष के नेता हों अथवा उनके अपने दल का साधारण कार्यकर्ता, सभी को बराबर सम्मान देना और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करना उनका स्वभाव था। अटलजी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर विफल किया। इस हमले के दौरान एवं आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में, चाहे फिर वह इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण का मामला ही क्यों न हो. अटलजी को पूरे विपक्ष का सहयोग प्राप्त रहा। उस समय के जिन गैर भाजपा नेताओं के साथ अटलजी के मधुर व्यक्तिगत संबंध थे, उनमें इन्द्रकुमार गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, डा. मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, आर. वेंकटरमण, शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल और डा. फारुख अब्दुल्ला प्रमुख थे। संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में सोमनाथ चटर्जी, शरद पवार एवं अन्य प्रमुख गैर भाजपा नेता बिना रोकटोक सीधे अटलजी के कमरे में प्रवेश कर सकते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और अटलजी में घनिष्ठ मित्रता थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनके प्रधानमंत्री काल में वेंकटरमण तमिलनाडु के राजनीतिक मामलों में उनके सलाहकार थे। सोमनाथ दा अक्सर अटलजी से मिलकर मित्र के नाते उनसे अपने दिल की बातें किया करते थे। इसी तरह कई बार देर शाम अटलजी कहते थे कि ज्योति बसुजी को फोन लगाओ और आप सब कमरे से बाहर जाओ। पूछने पर कि अटलजी आप कट्टर साम्यवादी नेता ज्योति बसु से आधे–पौन घंटे तक क्या बात करते हैं? अटलजी कहते थे, यह हम मित्रों की आपस की बात है।

शरद पवार भी अटलजी का बहुत सम्मान करते थे। अपनी राजनीतिक सूझ–बूझ के लिए प्रसिद्ध शरद पवार अटलजी से देश की राजनीतिक परिस्थिति पर विचार– विमर्श करते थे। अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल 2004 के बाद भी अक्सर अटलजी से मिलने आते थे और एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में बातें किया करते थे। भाजपा में जिन लोगों को अटलजी अपना मित्र कहकर पुकारते थे, उनमें लालकृष्ण आडवाणी और भैरोसिंह शेखावत प्रमुख हैं लेकिन घनिष्ठ पारिवारिक संबंध केवल आडवाणी जी के साथ थे। दोनों कभी भी एक–दूसरे के निवास पर भोजन इत्यादि के लिए पहुंच जाते थे।

आओ फिर से दिया जलाएं

भरी दुपहरी में अंधियारा
सूरज परछाई से हारा
अंतरतम का नेह निचोड़ें
बुझी हुई बाती सुलगाएं
आओ फिर से दिया जलाएं
हम पड़ाव को समझे मंजिल
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल
वर्तमान के मोहजाल में
आने वाला कल न भुलाएं
आओ फिर से दिया जलाएं
आहुति बाकी यज्ञ अधूरा
अपनों के विघ्नों ने घेरा
अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दधीचि हड्डियां गलाएं
आओ फिर से दिया जलाएं

राष्ट्र सुरक्षा के लिए अमर वीर योद्धाओं का सम्मान

—कर्नल टी.पी.एस. राना

'ए मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, जो मर मिटे वतन पे, उनकी याद करो कुर्बानी'। अभी हाल ही में हिमाचल के जिला मंडी के ही दो अमर वीर योद्धा नायब सूबेदार राकेश कुमार और हवलदार सुरेश कुमार ने भारत की सीमाओं पर, हम सब भारतीयों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम सबके लिए और हमारे प्रिय भारत के लिए, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर, इतिहास में अपना नाम लिखकर अमर हो गए। साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा तू अपना कर्म कर और अंतिम सांस तक युद्ध कर, तेरी जीत हुई तो तू इस पवित्र भारत भूमि पर राज करेगा और यदि वीरगति को प्राप्त हुआ तो तू स्वर्ग का अधिकारी होगा और इस धरा पर तुम्हें युगों युगों तक वीर योद्धा के नाम से जाना जाएगा। वीर योद्धाओं की चिताओं पर, लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नाम और निशां होगा। राष्ट्र और धर्म के लिए प्राणों की आहुति परम वैभव और स्वर्ग की प्राप्ति है। वह वीर योद्धा भाग्यशाली हैं जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते हैं। 'वीर भोग्या वसुंधरा' यानी वीर योद्धा ही इस धरती का भोग करने का अधिकारी है। खुदगर्ज और कायर इसका अधिकार खो देता है स राष्ट्र का हर नागरिक वीर योद्धा हो, तभी वह राष्ट्र अपने नागरिकों की सुरक्षा और संपन्नता सुनिश्चित कर पाता है।

स्वर्ग प्राप्ति, परम वैभव, परमधाम और फिर उसी परमात्मा में विलीन हो जाना हमारे सनातन ऋषियों की, जीवन भर की, कठोर तपस्या का ध्येय रहा है। यह अधिकार दूसरे किसी को अगर प्राप्त है तो वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए, वीरगति प्राप्त करने वाले, वीर योद्धाओं को मिला है। राष्ट्र के दूसरे नागरिक जो इतने सौभाग्यशाली नहीं होते वह इन वीरों की चिताओं पर जयकारा और श्रद्धा सुमन अर्पण करके अपने लिए सौ तीर्थ यात्राओं का पुण्य कमा सकते हैं स पुष्प की अभिलाषा में कवि ने क्या खूब लिखा है चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंधा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक।

इस लेख का मकसद ही भारत की जनता को इस परम सौभाग्य के कार्य से अवगत कराना और आने वाली पीढ़ियों में इस परंपरा को जिंदा रखना है। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कुछ स्कूलों, गांवों और पंचायतों ने इस परंपरा को बखूबी निभाया और जब इन वीर योद्धाओं की शव यात्रा टोली गुजरी तो आसमान को चीरता हुआ जयकारा और पुष्प वर्षा की। लेकिन मन में अत्यंत आक्रोश भी है कि कुछ स्कूल, गांव और पंचायतें इस पर खरी नहीं उतरी स प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन सभी से जवाब लेना चाहिए स पूर्व सैनिकों द्वारा, उन सभी को पहले ही सूचित कर दिया गया था और बताए गए जयकारा इस प्रकार थे—

1. भारत माता की जय।
2. वीर योद्धा...(नाम) अमर रहे...अमर रहे।
3. जब तक सूरज चांद रहेगा...(नाम) तेरा नाम रहेगा।
4. देश की रक्षा, अब कौन करेगाध्...हम करेंगे...हम करेंगे।
5. देश हमें देता है सब कुछ...हम भी तो कुछ देना सीखें।

कृपया इन जयकारों को जन—जन तक पहुंचाएं ताकि भारत की आने वाली पीढ़ियां भी इन वीर योद्धाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, सीमा पर खड़े अपने सैनिकों का सम्मान और ऐसे पुण्य के भागीदार बनना सीखें।

जो लोग शव—यात्रा या दाह—संस्कार के दौरान मुक—दर्शक बनकर बैठ जाते हैं उनसे बड़ा पाप का अधिकारी और राष्ट्र का अपमान करने वाला, दूसरा नहीं हो सकता स यहां तक कि कुछ जानता और नेता, दाह—संस्कार के दौरान सैनिक सम्मान गार्ड द्वारा, शोक शास्त्र के 2 मिनट के मौन से पहले और अंत में, अंतिम सैनिक सम्मान (सलामी शस्त्र) के समय भी मूकदर्शक बनकर बैठे रहते हैं। नेताओं से आग्रह है कि वह ऐसी अक्षम्य चूक ना खुद करें और ना ही जनता को करने दें। अमूमन देखा गया है कि, जनता अपने नेताओं जैसा ही आचरण करती है। ऐसे लोगों से आग्रह है कि वह इस

प्रकार का व्यवहार करके, भारत के इन वीरों का अपमान ना करें। नेताओं को न सिर्फ राष्ट्र के लिए, सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन वीरों का सम्मान करके, जनता के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए, बल्कि उनके शोक संतृप्त परिवारों को ताउम्र हरसंभव सहायता देने की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। सैनिक समाज भी, इसे राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर, ऐसे मौकों पर जनता को, इन नियमों से अवगत कराएं, तो ऐसी अक्षम्य चूक नहीं होगी। याद रहे, भारत के दुश्मन, भारत के तेजी से बढ़ते कदमों से अत्यंत परेशान हैं और विकास की इस गति को रोकने या धीमा करने के लिए, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सैनिक, जिन्होंने अपना संपूर्ण यौवन, राष्ट्र–सेवा में लगाया और खुद इस दर्द को झेला है, यह बखूबी जानते हैं कि भारत के हर नागरिक को राष्ट्र के प्रति समर्पण की, अपनी जिम्मेदारी समझनी और निभानी होगी, और हर पूर्व सैनिक उसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग, दे सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है 'द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए'।

आओ फिर से दिया जलाएं

आओ फिर से दिया जलाएँ
भरी दुपहरी में अंधियारा
सूरज परछाई से हारा
अंतरतम का नेह निचोड़ें
बुझी हुई बाती सुलगाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ...

हम पड़ाव को समझे मंज़िल
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल
वतर्मान के मोहजाल में
आने वाला कल न भुलाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ...

आहुति बाकी यज्ञ अधूरा
अपनों के विघ्नों ने घेरा
अंतिम जय का वज्र बनाने
नव दधीचि हड्डियां गलाएँ।
आओ फिर से दिया जलाएँ...

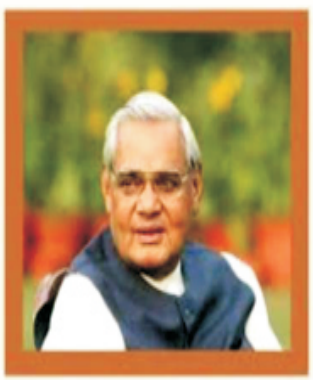

-अटल बिहारी वाजपेयी

संत अद्वितीय गंध वाले पुष्प

–हृदयनारायण दीक्षित

पीछे कई साल से भक्ति, भजन, कथा, प्रवचन काफी बढ़ गया है। सुंदर काण्ड या दुर्गा देवी की भक्ति के पाठ बढ़ गए हैं। संतों के दर्शन की जिज्ञासा बढ़ी है। सन्त सरल मनुष्य हैं लेकिन विरल हैं। अद्वितीय गंध वाले पुष्प। सन्तों को लेकर तमाम अविश्वसनीय कथाएँ चलती हैं। यह जिज्ञासा है। लोक का अपना सृजन। अपनी धारणा। अस्तित्व विराट है। असीम और अनन्त। सतत् विस्तारमान। अनिर्वचनीय और अव्याख्येय। हम इसी अस्तित्व के अंग हैं। क्या हम और यह अस्तित्व दो हैं? वेदान्त अनुभूति में अस्तित्व ही सत्य है, दूसरा कुछ है ही नहीं। उपनिषदों में अस्तित्व को ब्रह्म कहा गया है। स्वयं को भी अस्तित्व जानना ज्ञान की पूर्णता है। अस्तित्व पूर्ण है। इस पूर्ण में पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण बचता है। आत्मबोध इसी सम्पूर्णता का अनुभव है। ज्ञान यात्रा की शुरुआत हमेशा दो से होती है। एक विद्यार्थी और दूसरा यह अस्तित्व, संसार या विषय। ज्ञान के चरम पर दो नहीं बचते। लेकिन "ज्ञान यात्रा कठिन है"। यम ने नचिकेता को बताया था कि यह छूरी की धार पर चलने जैसी है। भक्ति तरल और सरल है।

प्रेम या भक्ति का प्रारम्भ भी दो से होता है। एक भक्त दूसरा आराध्य। एक भक्त और एक प्रभु या भगवान। भक्ति 'उसके' प्रति समर्पण से शुरू होती है। भक्ति में भी चरम पर भक्त भगवान हो जाते हैं। द्वैत मिट जाता है। भारत में दोनों मार्ग जाने गए हैं लेकिन सन्तों के बोध गीतों से भारत का आकाश भरा–पूरा है। ऐसे ही एक बोधयुक्त सन्त हैं रविदास। वाराणसी में उगे सन्त रविदास अनूठे हैं। संभवतः वाराणसी की धरती में अतिरिक्त सृजन वैभव है। इसीलिए यह देश की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ के विद्वानों ने भारतीय प्राक्ज्ञान का संरक्षण–संवर्द्धन किया। इसी सांस्कृतिक राजधानी में सन्तप्रवर रविदास का बोध स्थल है। काशी यों ही प्रणम्य नहीं है। थोड़ी दूर पर सारनाथ–बौद्ध तीर्थ। यहीं थोड़ी दूर पर कबीर। यहीं शंकराचार्य के प्रबोधन और यहीं रविदास की भक्ति। लेकिन अरस्तू, सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस या हिराक्लिटस जैसी वाणी गुनगुनाते रविदास विश्व आश्चर्य हैं। त्रासद जाति आवरण का अतिक्रमण करते रविदास। महाज्ञानियों को भी अपने बोध पुरुष होने का अहसास कराते सन्त रविदास भुलाए नहीं भूलते। रविदास गारंटी हैं कि ज्ञान, भक्ति और तप के क्षेत्र में जाति नहीं अन्तःकरण की ही जीत होती है। जाति, पंथ, मजहब मनुष्य के गढ़े विश्वास हैं। अन्तःअनुभूति में परम सत्य की दिव्यता है। उपनिषद् संस्कृत में हैं। जब वे उगे, रचे गए तब संस्कृत बोलचाल की भाषा रही होगी। रविदास के समय तक वे दुरूह हो गए।

रविदास और कबीर की अनुभूति–वाणी उपनिषद् अनुभूति जैसी। लेकिन रविदास या कबीर की वाणी में व्याकरण का डंडा नहीं। सीधी, सरल, निष्कलुष, पवित्र, जस की तस, निर्दोष और प्रवाहमान है। गाते हैं "प्रभु जी तुम दीपक हम बातीध्जाकी ज्योति बरै दिन राती।" उपनिषद् अनुभूति है कि वह परम सत्ता ज्योर्तिएकं है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और अग्नि जैसी ज्योतियों की भी ज्योति। लेकिन सन्त रविदास का समर्पण अनूठा है। वे परम सत्ता को दीपक और स्वयं को बाती गाते हैं। बाती को जलना ही है तिल–तिल। स्वयं की बाती को जलाकर ज्ञान–ज्योति पाने की

यह अभीप्सा ध्यान देने योग्य है। सन्त रविदास ने रामानन्द को गुरु माना। कबीर ने भी रामानन्द को गुरु माना लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि राजघराने के संस्कारों को धकियाते हुए लोकलाज खोने वाली मीरा ने रविदास को ही गुरु जाना। मीरा के भजनों की एक पंक्ति 'गुरु मिलिया रैदास जी' इसी तथ्य का प्रमाण है।

जीवन अनन्त यात्रा है। इस यात्रा में अर्द्धविराम भले ही होते हैं लेकिन भारतीय अनुभूति इसमें पूर्ण विराम नहीं मानती। हम सब अनन्त यात्री हैं। कहाँ से आए? कहाँ जाएँगे? कुछ पता नहीं। कबीर ने गाया है "रहना नहिं देश विराना है। यह संसार कागद की पुरिया बूंद पड़े धुलि जाना है।" यहाँ नहीं रहना। जाना ही है अनन्त यात्री होकर। यह संसार अनित्य है। शंकराचार्य भी यही कहते हैं। लेकिन रविदास के मन में उस लोक की गाढ़ी अनुभूति है। जहाँ से वे आए हैं उस अज्ञात लोक का अनुभव। रविदास की अनुभूति का यह लोक बड़ा प्यारा है। अमरत्व पूर्ण यह लोक वर्णहीन–जातिविहीन है– "जंहवां से आए अमर वह देशवांध्बांभन नाही, क्षत्रिय नाही शूद न बैसवाध्मुगल और पठान नाही सैय्यद न शेखवां।" बड़ा प्रीतिकर लोक है यह। वर्ण नहीं, पंथ, मजहब की पहचान नहीं। आरक्षण नहीं। सब एक अस्तित्व के विस्तार। अपने रस, रंग और उमंग में आनन्दमगन।

सन्त रविदास ऐसा ही भारत चाहते हैं। हम सब भी समता ममता से युक्त समाज के अभिलाषी हैं। भेदभाव रहित, वर्णहीन, एकरस, एक सुर, एक नाद व छन्दस् वाला मधुमय राष्ट्र। समरस अन्तस् में प्रवाहमान भारत। भारत ही क्यों समूचा विश्व भी। काशी में सन्त रविदास की बैठक है। भक्ति और ज्ञान की पीठ है उनका मन्दिर। उनके स्थल पर होना, स्मरण करना, दरश, परस पाना उपनिषद् ही तो है। उपनिषद् का अर्थ सरल और सीधा है–उप अर्थात निकट। नि का अर्थ है 'ठीक से' और षद् का अर्थ बैठना। रविदास यहाँ हैं अभी भी वर्तमान काल में ही। लाखों श्रद्धालु हर बरस आते हैं।

सन्त दिव्य चेतना के गहन ऊर्जा क्षेत्र से सम्बद्ध होते हैं। लोकमन सन्तों में रमता है। मनभावन कथाएँ भी गढ़ता है। रविदास मन्दिर में होने की बात ही दूसरी है। वे असाधारण सन्त हैं। वे संसार और परम सत्य के बीच एक सेतु हैं। इसके अलावा वे भारत के गगनमंडल में विराजमान सन्त नक्षत्रावलि के मध्य कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि सन्त भी हैं। ज्ञान और भक्ति किसी वर्ण जाति, गोत्र के विशेषाधिकार नहीं हैं। प्रेम प्रकृति की प्रकृति है और भक्ति है प्रेम की सम्पूर्णता का चरम परम। सन्त रविदास में भक्ति का परम सौन्दर्य था। भक्तिरस का अथाह सागर। वे हर दृष्टि से वरेण्य हैं।

भारत प्राचीन राष्ट्र है। इसका इतिहास दीर्घकाल में फैला हुआ है। इस इतिहास में अनेक उल्लासपर्व हैं तो अनेक दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड भी हैं। सामाजिक भेदभाव इतिहास की सबसे त्रासद घटना है। मनुष्य मनुष्य के बीच जाति वर्ण के भेदभाव से हमारी सांस्कृतिक चेतना आहत रही है। इस भेदभाव के बावजूद सन्तों ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्व की रक्षा की। तुलसी, सूरदास, दादू, सुन्दरदास पलटू, जगजीवन, लालनाथ आदि सैकड़ों सन्त गरीबी और उपेक्षा के बीच तत्वज्ञान को उपलब्ध हुए। सन्त रविदास इसी नक्षत्रावलि के बीच ध्रुवतारा हैं। उन्हें पंडितों ने भी स्वीकार किया। समूचे भारत ने भी। सन्त रविदास को श्रद्धालु भारत का नमस्कार है।

सम्पूर्णता के प्रति प्रेम ही भक्ति है। प्रेम सभी जीवों का अन्तःरस है। हम इसी रसानुभूति में किसी के भी प्रति प्रेमी हो जाते हैं। ऐसा प्रेम रूप से प्रारम्भ होता है। पहले रूप के प्रति आकर्षण, फिर आसक्ति फिर उस एक के प्रति अनन्य भावरस। भक्ति प्रेम की सम्पूर्णता है। यह सम्पूर्ण प्रेम है। अखंड, अविभाज्य और आत्मीय। भक्त सम्पूर्णता–अस्तित्व में अपना आराध्य देखता है और आराध्य में ही सम्पूर्ण को भी। जैसे ब्रह्मज्ञानी अपने चरम पर ब्रह्म हो जाते हैं वैसे ही भक्त भी अपने चरम पर भगवान। भक्तिरस की धारा में दो नहीं बचते। प्रेम गली अति सांकरीध्ता मे दो न समाय।

बांग्लादेश की मिलिट्री को 'पढ़ाएगा' पाकिस्तान

1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से मार भगाया था। 53 साल बाद फिर से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में लौटने लगी है। पाकिस्तानी सेना के जनरल साहब जल्द अपनी पूरी टीम के साथ बांग्लादेश के दौरे पर आ सकते हैं। यह सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन यह सच है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में वह खुद बांग्लादेश सेना के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन्फेंट्री एंड टैक्टिस स्कूल, डिफेंस सर्विस कमॉड का दौरा करने की इच्छा जताई। जनरल मिर्जा बांग्लादेश सेना के स्टाफ कॉलेज में युवा अफसरों को गेस्ट स्पीकर के तौर पर संबोधित करना चाहते है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस दौरे से संबंधित एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। हांलाकि तारीख का अभी एलान नहीं हुआ है।

नौसैन्य अभ्यास की तैयारी

शेख हसीना के जाने और यूनुस के आने के बाद से फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान करीब जाने लगा है। शेख हसीना ने साल 2022 में पाकिस्तानी वॉरशिप च्छै तैमूर को चिटगाँव में डॉक करने इजाजत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक अब बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ साझा अभ्यास की तायारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित होने वाले मल्टिनेशनल नेवल अभ्यास 'अमन 2025' में भी बांग्लादेश शामिल होने जा रहा है। दोनों के बीच बढ़ते सामरिक रिश्तों पर रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार (रि) का कहना है 'मौजूदा सरकार का हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान के साथ लगाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के राजनयिक है सैन्य संसथानो के प्रमुख उनका इस इच्छा को व्यक्त करनवा कि वो बंग्लादेश के साथ और करीबी रिश्ता चाहते है। यह भारत लिए एक चुनौती बनने वाली है'।

मोहम्मद यूनुस की दरियदिली

आजादी के 53 साल बाद फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान की शक्ल लेता जा रहा है। पहले पाकिस्तानी जमात ने शेख हसीना की सरकार गिराई। भारत के साथ दुश्मनी बढ़वाई और अब पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश को अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर चुका है। पाँच साल से जो इस्लामाबाद से ढाका की सीधी फ्लाइट बंद थी वो अब फिर से बहाल करने का एलान कर दिया गया है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के वीजा में भी छूट देने का एलान कर दिया है। इस दरियादिली के पीछे रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अशोक कुमार (रि) का कहना है 'पहले आईएसआई लुकछुप कर अपनी गतिविधियों को बांग्लादेश में अंजाम देता था। अब इस मौजूदा सरकार में वो खुलकर भारत विरोधी गतिविधियों अंजाम देगा'। बांग्लादेश पहले ही पाकिस्तान को जनवरी में आयोजित होने वाले ट्रेड एग्जिबिशन के लिए न्योता दे चुका है। पाकिस्तान से

कार्गो शिप बांग्लादेश के चिटगाँव पोर्ट पर सीधा पहुंचना। पाकिस्तान से आने वाले सामान के इंस्पेक्शन से भी छूट देना। मोहम्मद यूनुस की दरियादिली ही है।

आईएसआई का प्लान

बांग्लादेश में रिजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान के हाथ होने की खबरे पुष्ट चुकी है। आईएसआई ने इस पूरे खेल को रचा। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद से ही वह भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब करने की साजिश रच रहा था। शेख हसीना की सरकार का पतन करा कर वो अपनी साजिश में काफी हद तक सफल हो गया। पाकिस्तानी सेना के जनरल बांग्लादेश आने को हैं। डायरेक्ट फ्लाइट से आईएसआई एजेंट ढाका पहुंचने का पूरा इंतेजाम हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बचा काम खुद बांग्लादेश में रह कर लेगी। मतलब साफ है भारत के बगल में एक और पाकिस्तान बनना शुरू हो चुका है।

हो गई है पीर पर्वत-सी

हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए.

आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी,
शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए.

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में,
हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए.

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए.

मेजर दलपत सिंह शेखावत (हाइफा हीरो), मिलिट्री क्रॉस

—एन.एस. जोधा

मेजर स्व. श्री दलपत सिंह शेखावत हाइफा के भारतीय नायक थे। उनका जन्म 26 जनवरी1892को देवली हाउस, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, परिसर मारवाड जोधपुर में हुआ था। मेजर दलपत सिंह जी के पिताजी का नाम कर्नल हरि सिंह था। वे पाली के देवली गाँव के ठाकुर थे और विश्व प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी भी थे।

मेजर दलपत सिंह शेखावत ने अपनी स्नातक की पढ़ाई लंदन के ईस्टबोर्न कॉलेज से की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, दलपत सिंह शेखावत को 1912 में किंग्स कमीशन प्राप्त हुआ और वे जोधपुर की सेना में मेजर के रूप में शामिल हुए।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जोधपुर रेजिमेंट को इजराइल के हाइफा शहर पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। यदि ब्रिटिश सेना हाइफा को नहीं जीत पाती, तो पूरा इजराइल हिटलर के चंगुल में आ जाता। इसके लिए जोधपुर लांसर, मैसूर और हैदराबाद लांसरों की सहायता ली गई। यह एक असंभव सा काम था। मेजर दलपत सिंह शेखावत के कमांड में 5000 सैनिकों का एक समूह, लांसर और सबसे प्राचीन राइफलों, तलवारों और भालों के साथ घोड़ों पर सवार होकर युद्ध में उतरे थे।

ब्रिटिश भारतीय सेना का यह हिस्सा 1 लाख सैनिकों की नाजी सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। नाजी सैनिक बंकरों में छिपे हुए थे और स्वचालित मशीनगनों से लैस थे। लड़ाई दो दिनों तक जारी रही। युद्ध के दूसरे दिन के अंत तक हाइफा को जर्मन सेना से मुक्त कर लिया गया और 1500 से अधिक जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया गया। हाइफा शहर में ब्रिटिश ध्वज फहराया गया, लेकिन अफसोस, उसी दिन 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह शेखावत ने युद्ध के दूसरे दिन के अंत में अपनी जान बलिदान कर दी।

मेजर दलपत सिंह शेखावत को उनके अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था।

23 सितंबर को आज भी जोधपुर के देवली हाउस

और शहीद स्मारक पर शौर्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के कई स्थानों पर भी मेजर दलपत सिंह शेखावत को सम्मान के साथ याद किया जाता है।

जोधपुर के ऐतिहासिक स्थल गौरव पथ पर भी शहीद के नाम पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है, जहाँ हर वर्ष उनकी जयंती पर भव्य श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है।

उनके सम्मान में, भारतीय सेना के 61वें घुड़सवार दल ने जोधपुर लांसर के प्रतीक चिह्न को अपनाया है। दिल्ली के तीन मूर्ति चौक में मेजर दलपत सिंह शेखावत, श्री अनूप सिंह जोधा और हैदराबाद लांसर्स के कमान अधिकारी तीसरे स्थान पर हैं। अब इसतीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाईफा चौक नामित किया गया है।

एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का जोधपुरएक खंड 'देवली हाउस' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दलपत सिंह शेखावत देवली गाँव के ठाकुर थे।

इजराइल, ब्रिटेन और भारत सरकार ने हाइफा जीत दिवस के अवसर पर टिकट भी जारी किए हैं।

मेजर दलपत सिंह शेखावत को इजराइल के हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली है। उनकी वीरता की कहानी इजराइल की प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा बन चुकी है।

जय हिन्द।

उपभोक्तावाद के खतरे–संस्कृति पर हमला

उपभोक्तावाद की कई परिभाषाएँ उपलब्ध हैं इनमें जो परिभाषा मुझे श्रेष्ठ लगी वह है कि उपभोक्तावाद एक बीमारी है और पूँजीवादी अर्थव्यवस्था चाहती है कि सारी दुनिया इस बीमारी से ग्रस्त हो। वैसे यह बीमारी कोई सैद्धांतिक मात्र नहीं है बल्कि यह वास्तविकता में एक बीमारी में परिवर्तित हो जाती है–याने शारीरिक बीमारी में भी। यह एक प्रकार की साइको– सोमेटिक बीमारी भी सम्भव है। उपभोक्तावाद एक भौतिकतावादी समाज की रचना करता है जो अन्य सामाजिक या राष्ट्रीय मूल्यों की फिक्र नहीं करता। और सच तो यह है कि एक सीमा के बाद यह उपभोक्ता को भी कोई सुख या खुशी देने की अवस्था में नहीं रहता।

इसके कई आयाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण आयाम इस प्रकार हैं–

उपभोक्तावाद हमें आलसी बना देता है जैसे हम काउच पटेटो शब्द का प्रयोग करते हैं। हम शारीरिक श्रम से विमुख हो जाते हैं। खुद का भोजन तक नहीं पकाते। हर चीज हमें रेडीमेड चाहिए या उपयोग के लिए तैयार। रेडी टू यूज, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक – ऐसे कई उदाहरण हैं। रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव रसायनों का, नमक का या शक्कर का और अनावश्यक रसायनों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और यह लाइफस्टाइल बीमारियों के लिये जिम्मेदार है। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ सहज ही शरीर में प्रवेश पा सकती हैं।

उपभोक्तावाद लोगों में कम्पल्सिव बाइंग सिंड्रोम जैसी मानसिक बीमारी को जन्म देता है। इस बीमारी में उपभोक्ता को शॉपिंग या खरीददारी का एक प्रकार का नशा हो जाता है। बार बार मॉल में जाना, अनावश्यक खरीदी, खरीदी न करने पर डिप्रेशन जैसी समस्या – यह भी एक प्रकार की बीमारी है। इस तरह के कई मामले पश्चिमी देशों में रेकार्ड किये गए हैं।

सबसे पहले खरीदने की प्रतियोगिता जैसे सबसे पहले मूवी देखने की प्रतियोगिता होती थी। एक तरह की अनावश्यक प्रतियोगिता जो समाज में निराशा को जन्म देती है। न खरीद पाने की स्थिति में हीन भावना का जन्म होता है जो एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसके सामाजिक व आर्थिक पक्ष को भी हम समझेंगे।

उपभोक्तावाद इंसान की रचनात्मकता को धीरे–धीरे खत्म कर रहा है। जब सब कुछ तैयार मिलता है और रेडी टू डू किस्म में मिलता है, तो हम दिमाग के रचनात्मकता वाले हिस्से का उपयोग ही नहीं कर रहे होते हैं। जब हम किसी तरह के अभाव में कोई काम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस जरूरत को पूरा करने के लिये कई वैकल्पिक तरीके और सामग्री पर काम करता है। इससे नई खोज का जन्म भी हो सकता है। लेकिन तैयार उपभोक्ता सामग्री हमारे मस्तिष्क को किसी नई विधा पर काम करने से रोकती है। डू इट योरसेल्फ जैसे कुछ उत्पाद हमारे मस्तिष्क को नयापन देते हैं पर अल्प समय के लिए क्योंकि इसमें सारे घटकध्सामग्री रहती है और मस्तिष्क का सीमित पार्ट सीमित समय के लिए ही प्रेरित हो पाता है।

इसी तरह से उपभोक्ता में एक प्रकार की जमाखघेरी की लत लग जाती है जिसमें वह कोई सामान घर में

रखना जरूरी समझता है भले ही उसकी उपयोग की अंतिम तिथि के पहले उपयोग भी नहीं कर सके। उदाहरण के लिए मेहमान के आने पर, या सूचना मिलने पर हम मिठाई मँगाते थे लेकिन एक उपभोक्ता पहले किसी सोचता है कि मिठाई मँगा कर रखें– न जाने कब मेहमान आ जाए। भले ही मिठाई खराब हो जाए या स्वयं घर वाले ही खराब होने के पहले उसका उपयोग कर लें। ऐसा ही खरीदी का तरीका, बच्चों के लिये खरीदी के मामले में अपनाया जाता है। आज आपका फ्रिज छोटा पड़ता है क्योंकि उसमें आधी से अधिक वस्तुएँ वह होती हैं जो आप सिर्फ रखते हैं, नियमित उपयोग नहीं करते और इसीलिये हम कई बार बहुत महँगा सामान भी खराब हो जाने या उपयोग की तिथि निकल जाने के कारण फेंक देते हैं। पहले हम जरूरत के हिसाब से नजदीक की किराने की दुकान से सामान लेकर आते थे लेकिन अब महीने में सिर्फ एक बार जाकर बड़ी शोपिंग मॉल से सामान खरीदते हैं, जरूरत से अधिक खरीद लेते हैं– और यही एक पूँजीपति चाहता है, याने उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना।

शारीरिक और मानसिक बीमारियों के अलावा बहुत बड़ी समस्या सामाजिक एवं आर्थिक बीमारियों की है। उपभोक्तावाद हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति पर हमला करता है। भारत की सामाजिक व्यवस्था उपभोग की नहीं, उपयोग की है, स्वाबलंबन की है। हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि यह शुद्ध, भरोसेमंद व किफायती होता है। परम्परा से हम लोग पुनः उपयोग करने जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन्हें सुधार लेते हैं, उनका उपभोग करके फेंक नहीं देते। उपभोक्तावाद वस्तुओं के पुनरुपयोग के प्रति उदासीन है। क्योंकि यह उसे टर्नओवर नहीं देता बल्कि उसकी रफ्तार को कम कर देता है।

भारत में पेन भी रीफिल किए जा सकने वाले अधिक बिकते हैं लेकिन अब यूज एंड थ्रो किस्म के पेन भी बिकते हैं। जब हम रीफिल करने की जगह एक पेन को फेंक देते हैं तो हम उस पेन के अन्य हिस्से जैसे बॉडी, स्प्रिंग, ढक्कन आदि के साथ न्याय नहीं करते। इस तरह से चीजों को फेंक देना एक अलग अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। यही यूज एंड थ्रो का व्यवहार हमारे सामाजिक सम्बन्धों में भी दिखाई देने लगता है। यह स्वयं में बड़ी सामाजिक बीमारी है।

उपभोक्तावाद हमारे सोचने के तरीके को भी अधिक भौतिकतावादी बना देता है, हम वस्तुओं का अधिक उपभोग करते हैं, वस्तुओं की खपत बेतहाशा बढ़ती है और यही पूँजीवादी व्यवस्था को बल देने लगती है। हम एक दुश्चक्र में फँस जाते हैं।

किसी बड़ी होटल में प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहाँ वस्तुओं की कीमत बहुत अधिक होती है, इसका प्रचार होता है, और सच मानिये इस तरह की प्रदर्शनी में अधिकांश सामान ऐसा होता है जो रोजमर्रा के काम का नहीं होता बल्कि कभी–कभी उपयोग में लाने वाला होता है, या गृह सज्जा, मेक–अप, मँहगी ड्रेसेज आदि। यह सहज है कि सामाजिक परिवेश में यह जानने की उत्सुकता होती है कि क्या आपने वह प्रदर्शनी देखी, यदि देखी तो क्या खरीदा। क्योंकि यह बात अब उनके सामाजिक स्तर से जुड़ने लगती है। कोई गर्व करता है तो कोई शर्मिंदा होता है।

एक युवा का चयन मुश्किल प्रवेश परीक्षा के बाद एक महत्वपूर्ण पढ़ाई के लिए एक बड़े महाविद्यालय में हुआ। उस प्रतिभावान विद्यार्थी का प्रदर्शन बहुत ही जल्दी खराब होने लगा। एक वर्ष पूरा होने के पहले ही उसने उस पढ़ाई को छोड़ दिया। थोड़ी

तहकीकात से पता चला कि वह युवा विद्यार्थी स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिर नहीं कर सका। साथी विद्यार्थियों के मँहगे कपड़े, महँगी गाड़ियाँ, उनके खर्च करने का तरीका आदि उसे विचलित कर गए। प्रारम्भ में उसने प्रतियोगिता का प्रयास किया लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ने बहुत सहयोग नहीं किया। पहले निराशा, असंतोष और धीरे–धीरे अवसाद से ग्रस्त होकर उस युवा ने पढ़ाई छोड़ दी और उसका भविष्य कभी सँवर नहीं सका।

यूरोप में हाल ही में एक ऐसा उदाहरण सामने आया जहाँ एक महिला शॉपिंग माल से चोरी करने की आदत से ग्रस्त हो गई। प्रारम्भ में शॉपिंग और फिर धन नहीं उपलब्ध होने पर भी सामान के उपयोग की आदत की मजबूरी के कारण शॉप लिफ्टिंग करनी शुरू की और जल्द ही यह तरीका एक लत में बदल गया और इसकी परिणिति जेल जाने में हुई।

ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहाँ लोग इन सब कारणों से एक तरह के मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इन सब मानसिक रोगों के पीछे उपभोक्तावाद का भी हाथ है। अब देखिए इन सब का आर्थिक रूप से नुकसान कैसे होता है।

अधिक उपभोग करने की आदत :

आवश्यकता से अधिक उपयोग या उपभोग करने की आदत कई बार किसी विज्ञापन की प्रेरणा से भी लग सकती है। इसके कई उदाहरण उपलब्ध हैं। जो टूथपेस्ट हम केवल एक चने के बराबर उपयोग करके भी अपने दाँत साफ कर सकते हैं उसकी जगह वे चार गुना अधिक टूथ पेस्ट दृ ब्रश पर लगा हुआ दिखाते हैं। एक समय नीम की दातून से दाँत साफ करने वाला देश आज पूरी तरह टूथपेस्ट और ब्रश पर निर्भर हो गया है। इस मद पर लगभग शून्य खर्च करने वाला देश आज 12,000 करोड़ रुपए सालाना टूथपेस्ट और ब्रश पर खर्च करता है। उपभोग की जगह उपयोग करके हम काफी पैसा बचा सकते हैं। हालाँकि अभी भी भारत के 60 प्रतिशत से थोड़े ही अधिक लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं।

अनावश्यक वस्तुओं का उपभोग :

भारत में उपलब्ध स्थानीय विकल्पों के बावजूद भारत में ठंडे कार्बनेटेड ड्रिंक्स का बाजार बीस हजार करोड़ का है। यह लगभग पूरी तरह अनावश्यक खर्च जैसा है। ऐसे और भी कई उदाहरण मौजूद हैं।

उपभोक्ता, विभिन्न सामग्री को अनावश्यक जमा करने लगते हैं जिसमें उन्हें अतिरिक्त पैसे लगाने पड़ते हैं। इससे बचत का नुकसान होता है, एक प्रकार की जमाखघेरी भी होती है।

एक अन्य उदाहरण आलू की चिप्स का है। आलू उत्पादन के मौसम में शायद दस रुपए किलो भी नहीं बिक पाता है लेकिन आलू से बनाई गई चिप्स 300 रुपए किलो बिकती हैं। यह भी उपभोक्तावाद का उदाहरण है।

उपभोक्तावाद से पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। पहला पूँजीवादी निर्माता प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हैं और यह प्रदूषण संसाधनों की कमी में झलकता है।

(साभार उपभोक्ता फोरम)

काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, संरचना एवं रोचक तथ्य

काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। पवित्र गंगा नदी यहां दर्शन पूजन करने के लिए आते वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल एक निकटवर्ती स्थल पर किया गया मंदिरों से घिरा हुआ है। परिसर में के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के पवित्र शिव मंदिरों के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का शासक वाराणसी शहर को काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह काफी पुराना और एक भव्य मंदिर है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के हर कोने से भगवान शिव के भक्त यहां दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास–

विश्वनाथ मंदिर के भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया, यह अभी तक अज्ञात है। लेकिन इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन लिपियों और मिथकों में किया गया है। माना जाता है कि दूसरी ईस्वी में मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था जिसे बाद में एक गुजराती व्यापारी द्वारा बनवाया गया। 15 वीं एवं 16 वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। तब अकबर के ससुर राजा मान सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन हिंदुओं ने इस मंदिर का बहिष्कार किया क्योंकि राजा ने एक मुस्लिम परिवार में अपने पुत्री की शादी की थी। 17 वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया और एक मस्जिद बनवाया। मस्जिद के ठीक पीछे प्राचीन मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं। वर्तमान संरचना का निर्माण 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्या बाई होल्कर द्वारा एक निकटवर्ती स्थल पर किया गया था। 1983 से मंदिर का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर की संरचना–

मंदिर परिसर में छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला है, जो नदी के पास विश्वनाथ गली नामक एक छोटी सी गली में स्थित है। तीर्थस्थल पर मुख्य देवता का लिंग 60 सेमी लंबा है और एक चांदी की वेदी में रखी गई 190 सेमी की परिधि है। मुख्य मंदिर चतुर्भुज है और अन्य देवताओं के मंदिरों से घिरा हुआ है। परिसर में कालभैरव धंधापानी, अविमुक्तेश्वरा, विष्णु, विनायक, सनिष्करा, विरुपाक्ष और विरुपाक्ष गौरी के लिए छोटे मंदिर हैं।

मंदिर की संरचना के अनुसार, एक सभा गृह या संगम हॉल है, जो आंतरिक गर्भगृह में जाता है। पूज्यनीय ज्योतिर्लिंग एक गहरे भूरे रंग का पत्थर है जो कि मंदिर में एक चांदी के मंच पर रखा गया है। मंदिर की संरचना तीन भागों से बनी है। सबसे पहले भगवान विश्वनाथ या महादेव के मंदिर पर एक शिखर है। दूसरा स्वर्ण गुंबद है और तीसरा भगवान विश्वनाथ के ऊपर एक ध्वज और एक त्रिशूल है।

काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन लगभग 3,000 भक्त दर्शन के लिए आते है। कुछ अवसरों पर यह संख्या 1,000,000 और इससे भी अधिक हो जाती है। मंदिर के बारे में उल्लेखनीय 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर और सोने का गुंबद है। यहां शुद्ध सोने से बने तीन गुंबद हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में रोचक तथ्य–

काशी विश्वनाथ मंदिर को ष्स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिरष् भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर सोने के गुंबद लगे हुए हैं। इस मंदिर के लिए सोना पंजाब के सिख महाराजा रणजीत सिंह ने दान दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय महत्व है। आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, वामाख्यापा, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य साई बाबा और गुरुनानक सहित कई प्रमुख संत इस स्थल पर आये हैं। पवित्र नदी गंगा में नहाकर पूरे विधिविधान से विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि हर शिवभक्त अपने जीवन में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर आता है। विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है जो काले पत्थर से बना एक मंडप और शिवलिंग को समेटे हुए है। यह चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। मंदिर परिसर में कालभैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के छोटे छोटे मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं मंदिर में कुछ समय के लिए रुके थे और वे इस शहर के संरक्षक हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के कारण वाराणसी को बाबा भोले की नगरी या शिव नगरी कहा जाता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व–

पवित्र गंगा के तट पर स्थित, वाराणसी को हिंदू शहरों में सबसे पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शिव, विश्वेश्वर या विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही विशिष्ट और अद्वितीय महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा और गंगा नदी में स्नान कई तरीकों में से एक है जो मोक्ष (मुक्ति) के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार, दुनिया भर के हिंदू भक्त अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के इस स्थान पर आने की कोशिश करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अपार लोकप्रियता और पवित्रता के कारण, भारत भर में सैकड़ों मंदिरों को एक ही स्थापत्य शैली में बनाया गया है। कई किंवदंतियों में कहा गया है कि सच्चा भक्त शिव की पूजा से मृत्यु और सौराष्ट्र से मुक्ति प्राप्त करता है, मृत्यु पर शिव के भक्तों को उनके दूतों द्वारा सीधे कैलाश पर्वत पर उनके निवास पर ले जाया जाता है और यम को नहीं। एक प्रचलित धारणा है कि शिव स्वयं मोक्ष के मंत्र को विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से मरने वाले लोगों के कान में डालते है।

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा का समय–

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर भोर में ढाई बजे खुलता है। मंदिर खुलने के बाद सुबह तीन से चार बजे के बीच मंगला आरती होती है। यह बहुत विशेष प्रकार की आरती है, जिसमें शामिल होने के लिए शुल्क लगता है। इसके बाद सुबह चार बजे से ग्यारह बजे तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। 11.15 से 12.20 के बीच भोगी आरती होती है और मंदिर के देवालय का फाटक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दो बजे मंदिर फिर से खुलता है। सात बजे से सवा आठ बजे तक सप्तऋषि या सांध्य आरती होती है, नौ बजे से सवा दस बजे तक श्रृंगार आरती होती है और साढ़े दस बजे से 11 बजे के बीच शयन आरती होती है। रात ग्यारह बजे मंदिर बंद हो जाता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का अच्छा समय–

अगर आप वाराणसी सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो वाराणसी जाने का सबसे अच्छा जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और समय नवंबर से फरवरी के बीच सीढ़ियां डूब जाती हैं जिसके कारण होता है। बरसात के समय में गंगा का आप वहां का मनमोहक दृश्य नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा वाराणसी में मार्च से लेकर सितंबर माह तक गर्मी और उमस भी खूब होती है। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाने का उत्तम समय नवंबर से फरवरी के बीच है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है इसलिए यहां बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर भारत के अन्य शहरों या राज्यों से विभिन्न सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

Disgraceful, say veterans as Army HQ removes picture of historic surrender in Dhaka

-AJ Prabal

As Vijay Divas approaches on 16 December, the removal of an iconic 1971 war photograph from its prominent position at the Army headquarters in New Delhi has sparked attention.

A painting depicting an imaginary victory celebration at the Pangong lake near the Galwan valley in Ladakh has replaced the iconic photograph of the ceremonial surrender of Pakistani soldiers to the Indian Army on 16 December, 1971 in Dhaka following the liberation of Bangladesh.

The surrender followed a full-fledged war between India and Pakistan that lasted just about two weeks, during which the United States and China both sided with Pakistan and the United States sent its Seventh Fleet to the Indian Ocean to assist the Pakistani Navi.

As many as 90,000 Pakistani soldiers laid down their arms and the prisoners of war were brought back to India with full honour, detained in POW camps for a year or so before being returned as part of the Simla Pact.

While it is not clear when the photograph was removed from the army headquarters, veterans believe it is part of the 'decolonisation' drive undertaken by the BJP government for the past several years. The removal of the iconic photograph, however, is a serious mistake and an insult to the Indian armed forces.

The photograph of the surrender reflected a historic and comprehensive military victory and has inspired successive generations of officers and the ranks. Why would the government decide to remove it from its vantage position at the office of the Chief of the Army Staff (COAS) where military leaders from abroad and visitors liked to be photographed with the picture of the surrender as the backdrop?

No explanation has come yet from the ministry of defence or the defence minister. Veterans however have voiced their dismay at the development. They are distressed at the recent changes forced on the Indian armed forces in the name of 'decolonisation' and question the assault on military history, tradition and creed.

They believe that reasons are entirely political and the BJP government at the Centre wants to erase the memory of the 1971 victory so that they do not have to give credit to the then PM Indira Gandhi.

Veterans have also questioned the rationale behind the removal of what is known as the 'Chetwode Creed' too from the army headquarters. Field Marshal Philip Chetwode was the Commander in Chief of the Indian Army and is credited for setting up of the Indian Military Academy in Dehradun. The Chetwode motto is derived from an address the Field Marshal gave to the Academy in 1932.

"I would ask you to remember that you have come here to have your first lessons in three principles which must guide an officer of a National Army," the Field Marshal had said and laid down the three following rules to follow:

First: – The safety, honour and welfare of your country come first, always and every time.

Second: – The honour, welfare and comfort of the men you command come next.

Third: – Your own ease, comfort and safety come last, always and every time.

"I do not find anything colonial in what Field Marshal Chetwode said. In fact, his credo for officers is even more relevant today than in those times. And the cringeworthy amateurish Ladakh painting which imagines a victory, is no match for what the Indian Army actually achieved in Dhaka on 16 December, 1971," reflected military historian Man Aman Singh Chinna, the author of 'The Seven Heroes of the 1971 War".

Lt General H.S. Panag agreed and commented, "The photo/painting symbolising India's first major military victory in a 1000 years and also first as a united nation, in 1971, has been removed by a hierarchy which believes that mythology, religion and distant fragmented feudal past will inspire future victories."

Some of the veterans who weighed in pointed out that for the last 10 years the present BJP government has tried to project the Kargil war of 1999, when a BJP-led government headed by Atal Bihari Vajpayee was in power, as a more significant victory than the 1971 war.

Others recalled that PM Modi had claimed that he had taken part in the Bangladesh Liberation War and gone to jail; that it was just a matter of time before he claimed victory for the 1971 war too, a veteran sarcastically commented.

Also Read: BJP negating Indira Gandhi's contribution in 1971 war: Congress

"We are waiting for the BJP & its supreme leader to say that they and he liberated Bangladesh... the govt which itself has nothing to showcase is trying to fiddle around with history but forgets in the bargain that history, once written, cannot be erased by such childish acts of removing pictures. BJP wants to remove anything which the earlier govts did for the nation," said another veteran.

Others recalled how the present government had stubbornly refused to turn INS Vikrant, India's first aircraft carrier that played a stellar role in the 1971 war. It had decided to turn INS Vikrant as scrap. Was it also part of the mission to rewrite history and wipe out memories of Indira Gandhi?

At least one veteran pointed to the government's decision to link the biometrics of all personnel of the Indian armed forces with Aadhaar. He alleged that the Aadhaar details have since been shared with agencies with possible connections to foreign intelligence agencies.

"It takes a special kind of jaundiced thought process to remove your own military victory from public eye. Pandering to political whims has happened earlier in Indian military too but never at this scale. It is an insult to all those who fought and died in 1971 war and to the worthies in this photo," reflected a veteran.

The ceasefire between Israel and the Hezbollah is a win-win

-Maj. Gen. Harsha Kakkar

After protracted negotiations involving US and France, Israel and the Hezbollah have accepted a ceasefire. The ceasefire comes after over a year of fighting resulting in the loss of thousands of lives, mostly innocents. Presidents Biden and Macron mentioned in a joint statement that the agreement 'will cease the fighting in Lebanon, and secure Israel from the threat of Hezbollah and other terrorist organizations operating from Lebanon,' adding, 'will create conditions to restore lasting calm and allow residents in both countries to return safely to their homes.'

Benjamin Netanyahu, the Israeli PM mentioned, 'we will enforce the agreement and respond forcefully to any violation.' As per the agreement there would initially be a sixty-day ceasefire. The world welcomed the agreement as it ended one part of the conflict in West Asia. The conflict in Lebanon has thus far displaced over 1.2 million Lebanese as also 60,000 Israeli's. As per Lebanon there are over 3700 deaths, while Israel has accepted loss of 75 soldiers and 45 civilians.

UNSC resolution 1701 which ended the 2006 Israel-Hezbollah conflict was the basis for the current agreement. Similar to 2006, only Lebanese armed forces and UN peacekeepers would operate south of Lebanon's Litani River. This will imply that Hezbollah forces would retreat about 40 Kms from the border while Israeli forces would vacate Lebanon. Over the years, the 2006 truce was breached by both sides, with Hezbollah constructing underground structures and Israeli aircraft overflying Lebanon regularly.

Yet the truce held, till Hamas launched its raids on Israel on 07 Oct last year. It should be noted that both the ceasefires (2006 and current) are between Israel and Hezbollah, not Lebanon, implying that the world has accepted Hezbollah as a global entity, despite being designated as a terrorist group. The current ceasefire is a win-win for all sides involved in the conflict and hence there is hope that the same would hold.

For Biden, there is some achievement, though in the final stages of his presidency. Had this ceasefire been announced prior to elections, it is possible that it could have benefitted Kamala Harris. The US was being stretched to its limits, providing Israel and Ukraine with weapons and ammunition as also maintaining its own reserves for any future operations. Its defence-industrial complex was unable to meet rising demands.

Netanyahu officially announced three reasons for accepting the ceasefire. Firstly, it enables Israel to focus on Iran, its major adversary, secondly, the ceasefire comes as a 'breather' as also allows Israeli forces to 'replenish their stocks' and finally separates Hamas and Hezbollah operations. But there are multiple other reasons.

Israeli defence forces are exhausted. There are reports of reservists not reporting for duty. A CNN report mentions that Israeli forces 'issued 1,126 arrest warrants for ultra-Orthodox conscripts who have not responded to drafting orders.' The Israel supreme court had determined that ultra-Orthodox Jews cannot be exempt from military service.

An Israeli military spokesperson mentioned while commenting on drafting orders to ultra-Orthodox Jews, 'The IDF (Israeli Defence Force) is in need of soldiers. We touched on the figure of 10,000, but this isn't a stable figure because we have casualties unfortunately.' The ceasefire with Hezbollah will reduce demands on numbers being recruited. Further, there are disagreements within the Israeli government on its conduct of the conflict as also the end state desired by Netanyahu.

Israel has never been able to make the Hezbollah redundant. In 2006, prior to the ceasefire, both sides had suffered casualties, hence welcomed the ceasefire. It enabled them to live to fight another day. Israel learnt its lessons and attempted to implement them in this campaign. Hezbollah had also brought about changes and despite suffering a series of setbacks, managed to force another ceasefire.

In the present war, Israel eliminated members of the Hezbollah's senior leadership by target bombing and its unique 'pager bombs,' taking out their middle level leaders. Simultaneously, its air force bombed Hezbollah's rocket storage depots as also production facilities. However, these did little to stop the launch of rockets. Hezbollah had also learnt from 2006. In fact, days before the ceasefire, it fired a barrage of over 250 rockets into Israel.

Incursions into Lebanon have never been very successful for Israeli forces, either in 2006 or even now. Despite heavy casualties, the Hezbollah have always bounded back. Casualties for Israel are difficult to replace, especially when it continues to battle Hamas in Gaza. Lebanese civilian casualties in targeted airstrikes only benefit the Hezbollah as terrorist groups gain supporters with innocent deaths. Simultaneously, it impacts Israel's global standing.

Israel can now concentrate on Hamas, anti-Israel groups in Syria as also in Yemen. Israel is aware that the truce would enable Hezbollah to rebuild its structure as also its military power. It would ultimately have to engage with it sometime in the future. That may not be immediate, but will have to happen. It is a matter of time but has bought relief to citizens in both countries.

For Iran, the main backer of Hamas and the Hezbollah, it is essential that at least one of its proxies remains secure for the future. It has no choice but to sacrifice Hamas while saving Hezbollah. For Iran, Hamas, Houthis and the Hezbollah are buffers between it and Israel, its sworn enemy. It cannot let all of them be destroyed.

Simultaneously, Iran has opened negotiations with The International Atomic Energy Agency (IAEA), hoping to obtain sanction relief. This ceasefire would benefit it alongside its reproachment with its neighbours. Hence, it gave its sanction for the ceasefire to the Hezbollah chief, Naim Qaseem.

The Hezbollah also needs to recoup. Its enmity with Israel continues. For it the ceasefire is a pause as it rebuilds its capabilities, manpower, structures and stockpiles of munitions. While it has suffered casualties, it is aware that it has not lost the war, maybe the battle, and is preparing for the next phase.

In the ultimate analysis, both Israel and Hezbollah know that this is not a permanent peace agreement. For how long would it continue is anybody's guess. Currently, forces on both sides as also the population is weary of war. It is this weariness which may compel both sides to maintain peace at least for the near term.

The three dangers that India faces

-Bharat Verma

Very few policy makers in India dare to acknowledge the danger to the nation's territorial integrity. The security and integrity of the nation has become hostage to vote-bank politics. Democracy and more than eight percent economic growth will be of no avail if the country as such withers away.

India is not only being frayed at its borders by insurgencies, but its very writ in the heartland is becoming increasingly questionable. The rise of a nation is predicated upon unity, peace and stability, which are essentially determined by good governance.

The prevailing security scenario poses the serious question -- Is India's development and economic growth becoming unsustainable due to poor handling of the security? There are three dangers to the territorial integrity that bedevil the nation.

Danger-1

New Delhi and the state capitals have almost ceded the governmental control over 40 percent of the Union's territory to the Naxalites. The Naxals are aided and abetted by the crime mafia that runs its operations in the same corridor from Nepal to Andhra Pradesh, as well as Maoists of Nepal who in turn receive covert support from other powers engaged/interested in destabilising

India.

The nexus between the United Liberation Front of Assam and Maoists in Nepal is well established.

In a recent attack in Chhattisgarh, Maoists of India and Nepal were co-participants. There are also reports to suggest that Indian Maoists are increasingly taking to opium cultivation in areas under their control to finance their activities. The Maoist-crime-drug nexus is rather explosive.

Danger-2

The security forces, primarily the Indian Army, have held the state of Jammu and Kashmir physically since Independence. The politicians and the bureaucrats have contributed nothing to resolve the situation. The danger has since magnified many times as displayed by the presence of thousands of supporters of the Lashkar-e-Tayiba flying their flags in a recent rally of dissidents.

Under the garb of peace overtures, heavily armed infiltrators with tacit support from the Pakistan military-intelligence establishment continue to make inroads into Kashmir. They are at present lying low, waiting for an opportune

moment for vicious strikes on several fronts to undermine the Indian Union. This ghost force reared its head in a recent rally organised by Syed Shah Geelani. Pakistan and its sympathisers in India are working in a highly synchronised fashion for demilitarisation of the valley.

Simultaneously, there is an insidious campaign to malign the Indian Army on one pretext or the other as part of the psywar being waged by the ghost force under Islamabad's directions.

After all the wars, export of terrorism, inconsistent and weak policies by New Delhi, Islamabad could not win Kashmir only because the Indian Army held its ground. If the ghost force succeeds in making locals rise against the army, it will be an unprecedented achievement for Islamabad.

The talk of demilitarisation and the campaign to repeal Armed Forces Special Powers Act, are therefore merely ploys that aim to achieve the Kashmir objective even as the Pakistan establishment expands its tentacles not only within the valley but in other parts of India as well.

While the Pakistan dispensation talks of peace, terrorist cells are proliferating in the country including new frontiers in southern part of India. Islamic fundamentalism/terrorism footprints, as evidenced by the Bangalore-centered incidents, are too glaring to be ignored.

Islamic terrorism in the garb of freedom fighting in Kashmir is therefore de-stabilising the entire country. Islamabad is determined to use Kashmir as a gateway/launching pad to rest of India.

Danger-3

Given a modicum of political will, Danger-I and II may still be manageable, however, Danger III to its territorial integrity in the northeast may prove to be the most difficult. In fact the entire northeast can easily be unhooked on multiple counts from the Union. First, these are low populated areas having contiguity with the most densely populated and demographically aggressive country in the world, Bangladesh. The country has also emerged as a major source of Islamic fundamentalism which impacts grievously on the northeast.

To add to these woes, New Delhi because of sheer vote-bank politics legitimised illegal migration for 22 years through the vehicle of Illegal Migrants (determination by tribunals) Act, 1983. Many border districts now have a majority population constituting illegal immigrants from Bangladesh. In the near future, this leverage will be used to create an internal upheaval against the Centre as in the case of the valley.

It's a classic Islamic fundamentalist principle of asymmetric warfare. What cannot be achieved by conventional wars can be done through infiltration and subsequently internal subversion. They call it jihad!

Second, the northeast if not addressed appropriately could unhook from the Union before the valley given the acute vulnerability of the Siliguri Corridor, which is merely 10 to 20 kilometres wide and 200 kilometres long. If this critical corridor is choked or subverted or severed by force, the Union of India will have to maintain the northeast by air. With poor quality of governance for which the country is infamous, the local population may gravitate towards other regional powers.

Third, with China's claim over Arunachal Pradesh becoming more strident, as evidenced by its recent stance on Tawang, the danger to the Siliguri Corridor stands enhanced. This corridor has been facing internal turmoil for many years. The area may well be further subverted by inimical regional powers.

Chinese intention to bargain for Tawang to secure Tibet is deceptive. Subsequently, it would covet entire Arunachal Pradesh to protect Tawang. The Chinese are known for expanding their areas of strategic interests with time unlike the Indians who are in a tearing hurry to convert the Siachen Glacier into a 'mountain of peace' or the LoC into a 'line of peace' or equating Pakistan as an equal victim of terrorism.

It is a matter of grave concern that New Delhi

is so prone to issue statements without thinking it through, as long as it appeases the adversary even temporarily. Therefore, the northeast -- with the internal turmoil in the Siliguri Corridor, with low population surrounded by overpopulated Bangladesh exporting Islamic terrorism under tutelage of Islamabad, with China gaining influence in Nepal and Bangladesh and its upping the ante on Tawang -- the danger to the region is grave.

Manipur is a stark indicator. The insurgents have nearly weaned the state from the Indian Union. The writ of the Indian Union has ceased to operate; insurgents, compelling people to turn to South Korean music and films, ban Hindi music and films.

New Delhi continues to fiddle while the northeast burns which in turn poses a grave problem to the territorial integrity of the Union of India. The world once again is getting polarised into two camps after the end of the Cold War -- democracies and authoritarian regimes of all hues, which includes Islamists, Communists, and the Maoists. Their perspectives are totally totalitarian. Therefore with China, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, and Nepal (Maoists), being neighbours, the danger to the Indian territorial integrity stands enhanced.

Netaji Subhas Chandra Bose – Early Life

He was born in Cuttack in Odisha on 23rd January 1897 to Janakinath Bose and Prabhavati Devi. He was a bright child and showed determination and promise. His father was an eminent lawyer and was given the Title Rai Bahadur by the British. Subhash did his schooling in his hometown. After passing out from Ravenshaw-Collegiate-School, he joined the Presidency College Calcutta. At the young age of 16, he read books by Swami Vivekananda and Ramkrishna Paramhans. Their writings influenced him profoundly. He completed his higher studies in England at Cambridge University. He cleared the civil service examination in England in 1920, but in 1921 knowing about the Indian Nationalist Movement, he dropped his candidacy and returned to join the movement.

Netaji - Achievements, Works, and Contributions

After returning to India, he joined the Non-Cooperation Movement initiated by Mahatama Gandhi against the British. During that period, INC had become an influential non-violent organization. While Subhash Bose was working for the Non-Cooperation Movement, Gandhiji asked him to work with Chittaranjan Das. He later became Subhas Bose's political Guru.

Became commandant of the Bengal Congress volunteers.

While working for the Freedom Movement, he was imprisoned several times. In 1927 when he was released from prison, he started a newspaper, swaraj.

Later he was appointed General Secretary of the Congress party and started working with Jawaharlal Nehru.

In 1938, he became the President of the Indian National Congress. A planning committee was formed under him. This committee prepared an industrialization policy.

In 1939 all India forward block – a left-wing Nationalist party under the tutelage of Subhash Chandra Bose, became a faction of the Congress. The forward block party aimed to bring together all the radical members of the party.

He formed the Azad Hind Fauj, also referred

(Rest on page 35)

Soft power may not be enough to resolve India-Bangladesh ties

-Lt Gen Dushyant Singh

Since Bangladesh's inception, India has played a critical role in aiding its economic and social development. However, the recent political upheaval in Bangladesh has jeopardized the hard-earned progress in bilateral relations.

Bangladesh has been in the news over the past few months for all the wrong reasons. Initially, its developments primarily had an internal impact, but since Md. Yunus assumed leadership of the country, the situation has deteriorated further, with significant repercussions on India-Bangladesh relations. The Indian Foreign Secretary visited Bangladesh to explore possibilities for mending ties. However, the chances of success post this visit appear slim, given the anti-India stance of the Chief Advisor of Bangladesh's caretaker government.

India has long strived to foster harmonious relations with its neighbours, despite grappling with significant internal and external challenges. This commitment has been evident throughout history, notably in India's pivotal role in the liberation of Bangladesh in 1971. The 1971 India-Pak war not only dealt a comprehensive defeat to Pakistan but also ensured the creation of Bangladesh, a move that exemplified India's dedication to regional stability and justice.

Since Bangladesh's inception, India has played a critical role in aiding its economic and social development. Whether through supporting trade, providing humanitarian assistance during the pandemic, or resolving contentious issues like boundary demarcation and river water sharing, India has consistently gone beyond the call of duty to assist its neighbours. This cooperative stance underscores India's vision of mutual growth and prosperity in South Asia.

However, the recent political upheaval in Bangladesh has jeopardized the hard-earned progress in bilateral relations. The ouster of Sheikh Hasina's government in August 2023 and the subsequent appointment of Nobel Laureate Md Yunus as the head of the caretaker government were initially seen as a potential turning point. It was expected that Yunus would stabilize the internal situation, restore peace, and pave the way for free and fair elections. Instead, his tenure has ushered in political chaos and widespread unrest, threatening the very fabric of Bangladesh's social and economic stability.

Under Yunus' leadership, extremist groups such as Jamaat-e-Islami have been allowed to operate freely, leading to alarming atrocities against minorities, particularly Hindus. The Hindu population in Bangladesh, which constituted about 33% at the time of Partition, has now dwindled to a mere 7-8%. This decline is a direct result of decades of targeted killings, discrimination, and forced displacements, which have intensified in recent months. Temples are being desecrated, communities terrorized, and families driven to

flee the country, all under the apparent indifference of the current caretaker government. Incidentally, this government's mandate is to carry out essential electoral reforms and hold elections at the earliest. However, the way Yunus is giving statements in the media this does not seem likely in the near future. In addition to these human rights violations, the government's failure to address pressing economic issues has further destabilized the nation. Inflation is spiralling out of control, and foreign exchange reserves have plummeted to $18 billion, barely enough to sustain trade for 14 months. Moreover, efforts to erase the legacy of Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of Bangladesh, by removing his images and monuments, reflect a disturbing attempt to rewrite the country's history and undermine its foundational values.

The repercussions of this turmoil are being felt far beyond Bangladesh's borders, particularly in India. The plight of the Hindus in Bangladesh has sparked outrage in India, with demands for immediate intervention. The deteriorating situation also poses a significant security threat, with the potential for a massive influx of refugees, increased infiltration by terror groups backed by Pakistan's ISI, and heightened Chinese influence exploiting the instability in Myanmar and Bangladesh. These developments could severely impact the north eastern states of India, already a sensitive region.

In light of these challenges, India's response will be crucial in shaping the future of its relationship with Bangladesh and ensuring regional stability. The visit of India's Foreign Secretary to Bangladesh offered an opportunity to address these pressing issues diplomatically. However, given Yunus' apparent disregard for India's concerns and his failure to take decisive action, the prospects for meaningful progress seem bleak.

Historically, India has refrained from employing hard power in dealing with its neighbours, except in cases involving its northern and western frontiers. This restraint aligns with Chanakya's principle of prioritizing non-military means to achieve national objectives.

However, Chanakya also emphasized the use of all available tools, including force if necessary, to protect national interests. The current situation in Bangladesh may warrant a shift from India's traditional approach, invoking Chanakya's doctrine of sham (diplomacy), daam (economic incentives), bhed (division), and dand (punishment).

To address the crisis, India must adopt a multifaceted strategy leveraging its diplomatic, informational, military, and economic (DIME) tools. Diplomatically, India should engage with international partners to exert collective pressure on the Yunus government to uphold human rights and ensure minority protection. Economic measures, including targeted sanctions and conditional aid, could incentivize policy changes. Simultaneously, India must strengthen border security to prevent illegal infiltration and prepare its military for potential contingencies.

The situation also demands a "whole-of-nation" approach, involving not just the government but also civil society, think tanks, and the media, to build a unified response. India's leadership must clearly convey to Bangladesh that continued instability and hostile actions will have serious consequences. At the same time, India should reaffirm its commitment to supporting a stable and prosperous Bangladesh, emphasizing the shared history and mutual benefits of cooperation.

The stakes are high, and the path ahead is fraught with challenges. Yet, India's resolve to safeguard its national interests and uphold its values of justice and inclusivity must remain unwavering. Whether through dialogue, economic leverage, or, if necessary, decisive action, India must ensure that the current crisis in Bangladesh does not undermine the region's peace and stability. The time has come for India to assert its role as a responsible regional power and take the necessary steps to address this critical situation by all possible means.

Cousins at war': Pakistan-Afghan ties strained after cross-border attacks

-Abid Hussain

Islamabad, Pakistan: Pakistan's air raids inside Afghanistan on Monday amid rising tensions between the neighbours have injected new uncertainty into ties, say analysts.

The early morning attacks on Monday from Pakistan, according to a detailed statement by the Pakistani foreign ministry, were aimed at hideouts of armed groups including the outlawed Tehreek-e-Taliban Pakistan (Pakistan Taliban, or TTP). Afghan officials said eight people in all — five women and three children — were killed.

The official government statement said that the "terrorists" pose a great threat to the country, and alleged that "they have consistently used Afghan territory to launch terror attacks inside Pakistani territory."

"Terrorist groups like TTP are a collective threat to regional peace and security. We fully realise the challenge Afghan authorities face in combating the threat posed by TTP. Pakistan would therefore continue to work towards finding joint solutions in countering terrorism and to prevent any terrorist organisation from sabotaging bilateral relations with Afghanistan," the statement said.

The air raids came two days after a group of suicide bombers targeted a Pakistani military checkpost in its North Waziristan district, a border area next to Afghanistan, killing at least seven Pakistani soldiers.

The Afghan Taliban, who have ruled the country since taking over in August 2021, reacted swiftly to the Pakistani attacks, calling them "reckless". Hours after the air raids, the Afghan military fired mortar shells on Pakistani military positions near border districts, which left four civilians and three soldiers injured.

Zabiullah Mujahid, the Taliban government spokesperson, denied that foreign armed groups are allowed to operate from Afghan soil. But he conceded that parts of the border between Pakistan and Afghanistan were hard to control.

"In this regard, we have made our utmost effort and continue to do so; but one thing we must accept is that Afghanistan shares a very long border area with Pakistan, and there are places with rugged terrain including mountains and forests, and places that might be out of our control," Mujahid said in response.

Sami Yousafzai, a journalist and a longtime observer of Pakistan-Afghanistan ties, described the spat as a fight between two cousins.

"These two neighbours act like they are cousins. They cannot leave each other, but they cannot find a way to fix their relationship either. And in all this fighting, it is impacting the public-to-public relations between them," he told Al Jazeera.

For years, Pakistan was seen as a patron of the Afghan Taliban, which first rose to power in 1996. It was believed to hold considerable sway

on the Taliban leadership, whom it sheltered, funded and shielded diplomatically.

Yet amid the United States's so-called "war on terror", the Pakistan Taliban emerged and started waging a war against the state of Pakistan, although the group was ideologically aligned with the Afghan Taliban.

The Pakistani army conducted multiple operations to eliminate the Pakistan Taliban, and managed to push some of its leaders into Afghanistan. After the Afghan Taliban returned to Kabul in late 2021, Pakistan hoped to use its historic influence over the new Afghan rulers to contain the Pakistan Taliban.

Instead, attacks grew, and 2023 was among the bloodiest years in recent Pakistani history, with more than 650 attacks across the country, killing nearly 1,000 people, mostly from law enforcement agencies and the military. Most of the attacks on security personnel were claimed by the Pakistan Taliban, along with other relatively lesser-known armed groups.

Over the years, Pakistan has blamed the Pakistan Taliban for several attacks inside its territory, killing thousands of people, including the deadly attack on Army Public School in Peshawar in 2014, which killed more than 130 students. More than 90 percent of the attacks in 2023 were carried out in the northwestern province of Khyber Pakhtunkhwa and the southwestern province of Balochistan, both of which border Afghanistan.

Syed Akhtar Ali Shah, a former police chief in the Khyber Pakhtunkhwa province, said that such regular attacks against security personnel affects the motivation of the forces and Pakistan had little option but to retaliate.

Shah also noted that Pakistan had the added experience of a similar level of cross-border action earlier in the year against Iran, which perhaps emboldened the military.

In January this year, Iranian forces launched a cross-border attack inside Pakistan, targeting hideouts of an armed group that it claimed works against the interest of state of Iran.

Within 24 hours, the Pakistani government responded with attacks of its own inside Iran's Sestan-Baluchestan province, targeting what it claimed was armed groups seeking protection in Iran.

After the tit-for-tat action, Pakistan and Iran managed to calm those tensions, with the Iranian foreign minister visiting Pakistan the same month.

Shah, the former police chief, believed that Pakistan perhaps learned a lesson from that incident and decided to show "muscle". But he also added a word of caution.

"When you take an aggressive stance like that, it helps to have a dialogue from a position of strength. But it could backfire, as well, and lead to a dilemma for the country because the Afghan government can retaliate," he added.

Yousafzai said one way that the Afghan government could show its ability to hit back was by allowing the Pakistan Taliban a freer reign in the border areas.

"There is a lot of resentment within Afghanistan for what Pakistan did, and they are unhappy with the situation so this could have consequences," he said.

Shah said Pakistan does have some leverage on Afghanistan: Pakistan is landlocked Afghanistan's biggest trading partner. Pakistan has also long hosted millions of Afghan refugees. Many Afghans also travel to Pakistan to access health facilities.

Last year, following the surge in violence, Pakistan launched a drive to push Afghan refugees living in the country back to Afghanistan, citing security concerns.

The move was denounced, both domestically and globally, but more than half a million Afghans had been deported as of December 2023.

But if Pakistan uses any of those levers of influence, it is likely to end up even more unpopular in Afghanistan.

"There are strong anti-Pakistan sentiments in Afghanistan, and vice versa, and all of this isn't going to help in the long-term for either of the two," Yousafzai said.

Afghan Taliban hit 'several points' in Pakistan in retaliation for attacks

-Courtesy Hussain (Al-Jazeera)

Afghan Taliban forces have targeted "several points" in neighbouring Pakistan, Afghanistan's Ministry of Defense said, days after Pakistani aircraft carried out aerial bombardments inside the country.

The statement from the defence ministry on Saturday did not directly specify that Pakistan was hit, but said the attacks were conducted "beyond the 'hypothetical line'" – an expression used by Afghan authorities to refer to a border with Pakistan that they have long disputed.

"Several points beyond the hypothetical line, serving as centres and hideouts for malicious elements and their supporters who organised and coordinated attacks in Afghanistan, were targeted in retaliation from the southeastern direction of the country," the ministry said.

Asked whether the statement referred to Pakistan, ministry spokesman Enayatullah Khowarazmi said: "We do not consider it to be the territory of Pakistan, therefore, we cannot confirm the territory, but it was on the other side of the hypothetical line."

Afghanistan has for decades rejected the border, known as the Durand Line, drawn by British colonial authorities in the 19th century through the mountainous and often lawless tribal belt between what is now Afghanistan and Pakistan.

No details of casualties or specific areas targeted were provided. The Pakistani military's public relations wing and a spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs did not immediately respond to requests for comment.

Al Jazeera's Abid Hussain, reporting from Islamabad on Saturday afternoon, said there had been no official response from the Pakistani authorities on the attacks.

urity source told the AFP news agency that at least one Pakistani paramilitary soldier was killed and seven others wounded in cross-border exchanges of fire with Afghan forces.

Sporadic clashes, including with heavy weaponry, erupted overnight between border forces on the frontier between Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan and Khost province in Afghanistan, officials from both countries said.

The incidents come after Afghanistan's Taliban authorities accused Pakistan of killing 46 people, mainly women and children, in air strikes near the border this week.

Islamabad said it had targeted hideouts of fighters along the border, while Afghan authorities warned on Wednesday they would retaliate.

The neighbours have a strained relationship, with Pakistan saying that several attacks on its territory have been launched from Afghan soil – a charge the Afghan Taliban denies.

The Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – which shares a common ideology with its Afghan counterparts – last week claimed a raid on an army outpost near the border with Afghanistan, which Pakistan said killed 16 soldiers.

"We desire good ties with them [Afghanistan] but TTP should be stopped from killing our innocent people," Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif said in a cabinet address on Friday.

"This is our red line."

Al Jazeera's Hussain explained that Pakistan had hoped for good relations with the Taliban after the group's 2021 takeover of Afghanistan – and for attacks by TTP in Pakistan to be controlled.

But the relationship has deteriorated amid the uptick in violence.

Hussain said more than 950 Pakistanis, including security personnel and civilians, have been killed in 2024 alone.

Netaji Subhas Chandra Bose... (remainder of page 29)

to as the Indian National Army.

After Japan occupied most South-East Asia countries by defeating the British, the Indian National Army was formed. Soldiers were recruited from the prisoners of war liberated from the clutches of the British. The aim of forming the army was to liberate India from British rule.

In 1941 Subhash Chandra Bose escaped from India and reached Germany. In 1943 he went to Singapore and started recruiting the army

The Azad Hind Fauj contained about 45000 soldiers. It was comprised of Indian prisoners of war and Indians who were settled in countries of South-East Asia and had offered themselves to fulfil the nation's purpose.

Netaji hoisted the Indian Flag in Andaman, which the Japanese had occupied.

In 1944, the Azad Hind Fauj also attacked the North Eastern regions of India to win it back from the British.

Indian women, too, participated actively in the freedom struggle. There was a women's regiment of Azad Hind Fauj that actively participated in battles and attacks against the British. Captain Lakshmi Swaminathan commanded the regiment, and the all-women regiment performed with valour under her.

Subhash Chandra Bose organised the Azad Hind Fauj to oppose and fight the British and liberate his country with support from Japan. During this period, he also sought help from Hitler and Mussolini. He also founded the Free India Center in Berlin. He was attached to the India special bureau, which broadcasted the German-sponsored Azad Hind Radio.

Death of Subhash Chandra Bose

The unceasing endeavour of Subhash Bose came to an end with his demise. Throughout his life, he strived to free his motherland from the shackles of slavery and sacrificed himself on the altar of duty. He suffered third-degree burns in a plane crash and died on 18th August 1945 in a hospital in Taiwan.

गतिविधियां (Social Activities)

– जे. बी. एस. चौहान

झारखंड (कोंडागांव)

विजय दिवस का कार्यक्रम 16 दिसम्बर से सम्पूर्ण प्रदेश में पारम्परिक हर्ष और उल्लास से विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। जिसमें सबसे प्रमुख आयोजन नक्सल प्रभावित कोंडागॉव में 16 दिसम्बर को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ले.जनरल वी के चतुर्वेदी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे।

3 दिवसीय कार्यक्रम में दि. 15 दि को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत एक रोड शो से किया गया जिसमें आगे निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा पारम्परिक वेशभूषा में लोक नृत्य कर रहे थे। स्थान–स्थान पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि एक खुले वाहन में थे, उनका स्वागत स्थानीय लोगों विशेष रूप से माताओं ने आरती व माल्यार्पण से किया।

16 दि. को सुबह 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रांगण में पीटी की रिपोर्ट दी गई जिसमें कोंडागांव जिले के 457(373 युवतियाँ) प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने प्रशिक्षण का निरीक्षण करने का बाद युवाओं का मार्गदर्शन किया।

रीवां (मध्य प्रदेश)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला रीवा और नवगठित जिला मऊगंज इकाई के तत्वावधान में 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना द्वारा अद्वितीय अदम्य शौर्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन सेना पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया उसी उपलक्ष्य मे विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया।। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक श्री प्रदीप पटेल जी थे। अध्यक्षता परिषद के प्रदेश संरक्षक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय सचिव व प्रांतीय महासचिव सार्जेंट रमेश पाण्डेय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष व रीवा जिला महासचिव कैप्टन बी जी शर्मा जी, वरिष्ठ समाजसेवी राजा रमेश सिंह जी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती सिसोदिया जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष व सीधी जिले के अध्यक्ष कैप्टन धीरेश सिंह जी और समाजसेवी एडवोकेट प्रदीप सिंह जी रहे थे।

राष्ट्रीय सचिव एवं जिला रीवा इकाई के समस्त पदाधिकारियों के साथ जिला मऊगंज इकाई के पदाधिकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और अनुशासित दिव्य कार्यक्रम के आयोजन की बधाई व धन्यवाद ज्ञापित किया।

धुले (महाराष्ट्र)

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धुले में 16 दिसम्बर 2024 को विजय दिवस (1971) के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान धुले स्थित शहीद अब्दुल हमीद स्मारक पर फूल माला चढ़ाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गयी।

पुणे (महाराष्ट्र)

'विजय दिवस' का आयोजन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पुणे, महाराष्ट्र द्वारा 'एस.पी. कॉलेज, पुणे' में किया गया। समारोह का मुख्य आकर्षण 1971 के युद्ध के वास्तविक युद्ध नायकों की उपस्थिति थी। ब्रिगेडियर आप्टे और ब्रिगेडियर गोखलेर की उपस्थिति में समारोह हुआ। ब्रिगेडियर गोखले उत्तरी क्षेत्र में कहीं बटालियन कमांडर थे। 'मेजर हेमन्त मांजरेकर' पाकिस्तान पर हमला करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। ब्रिगेडियर उस घटना को याद करते–करते पुरानी यादों में खो गए और बेहद भावुक हो गए। अन्य ब्रिगेडियर आप्टे ने दुश्मन के साथ लड़ाई को इतने प्रभावी ढंग से विस्तार से बताया कि उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित हो गए। उनकी बटालियन के तीन सैनिकों को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला।